RNI No. : TNHIN/2013/52520 ■ वर्ष - 14 ■ अंक - 10 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » शनिवार » 01-08-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 भारत राष्ट्र महान, मेरा देश कमजोर ना हो : देवनानी

6 आंदोलन की संस्कृति : अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी आवश्यक

7 एक्ट्रेस से अब प्रेजेंटर बनीं सोनाली बेंद्रे

फर्स्ट टेक

अल्जीरिया में बस के गहरी खाई में गिरने से 25 लोगों की मौत

अल्जीयर्स/एपी। अल्जीरिया में शुक्रवार को एक बस दुर्घटना में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 अन्य घायल हो गए। अल्जीरिया के नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली। बस यात्रियों को सेतीफ से अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स ले जा रही थी जो अल्जीयर्स से लगभग 50 किलोमीटर दूर एल कर्मा क्षेत्र में सड़क से फिसल कर एक गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई ।

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

सियासी गठबंधन

कैसे मेंढ़क तुले तराजू,
पड़ा अक्ल पर सबके कोड़ा।
टांग खेंचते इक दूजे की,
चले अढ़ाई घर ज्यूं घोड़ा।
गिद्ध भोज में जुटे जीमने,
भुक्कड़ कोई ज्यादा-थोड़ा।
लगे सियासी गठबंधन यूं,
भानुमती ने कुनबा जोड़ा।।

गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष का संसद में हंगामा, बैठक दिन भर के लिए स्थगित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संसद में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा किया जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही लोकसभा ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। निचले सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। वे आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, ''कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, यह सदस्यों का समय है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिये। आप सदन को चलने दें।'' उन्होंने कहा, ''आज प्रियंका (गांधी) जी का भी प्रश्न होना है और वह प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं।'' बिरला ने कहा, ''कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल-बदलकर आते हैं उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं।''

सदन में निर्दलीय सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को आज साधुओं की तरह भगवा वस्त्र पहने हुए देखा गया। शोर-शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण अब तक प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं।

मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष बर्नहम से बातचीत की

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष एंडी बर्नहम ने शुक्रवार को भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को ''नई ऊंचाइयों'' पर ले जाने और हाल ही में लागू हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते से मिलने वाले व्यापार और निवेश के अवसरों का पूरा लाभ उठाने का संकल्प लिया। मोदी और बर्नहम ने फोन पर बातचीत के दौरान दोनों देशों के संबंधों के अहम पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने बर्नहम को शीर्ष पद संभालने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, ''हम प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों से लोगों के आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सहमत हुए।'' मोदी ने कहा, ''हम दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और कल्याण के लिए हाल ही में लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते से पूरा लाभ उठाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे।''

कावेरी विवाद : कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 13 को 'कर्नाटक बंद' का आह्वान किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/भाषा। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने शुक्रवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के उस निर्देश के विरोध में 13 अगस्त को पूरे कर्नाटक में बंद का आह्वान किया, जिसमें राज्य को तमिलनाडु के लिए 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया है। तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में रणनीति तय करने के उद्देश्य से बेंगलूरु में कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता वाटाल नागराज के नेतृत्व में विभिन्न कन्नड़ समर्थक संगठनों की बैठक के बाद यह घोषणा की गई।

यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक 'कर्नाटक बंद' रखा जाएगा।

आम जनता से इस बंद में सहयोग और समर्थन देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, ''आइए हम सब मिलकर बेलगावी से लेकर चामराजनगर तक 'कर्नाटक बंद' को पूरी तरह सफल बनाएं।'' नागराज ने राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए कावेरी जल आदेश का इस्तेमाल कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों ने तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने का विरोध करते हुए दलील दी है कि कर्नाटक खुद जल संकट का सामना कर रहा है और ऐसे में पानी छोड़ने से राज्य के किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने तमिलनाडु को रोजाना 15 दिन तक 3,500 क्यूसेक पानी देने की कावेरी जल विनियमन समिति की सिफारिश को बरकरार रखा है।

भिवंडी में चार मंजिला इमारत ढह गई, नौ लोगों की मौत

ठाणे/भाषा। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्थानीय नगर निकाय द्वारा खतरनाक' घोषित एक चार मंजिला इमारत के ढहने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई तथा दो. तीन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि पावरलूम नगरी भिवंडी में बालाजी नगर क्षेत्र स्थित कोहिनूर बिल्डिंग का एक हिस्सा बृहस्पतिवार रात 11 बजकर 20 मिनट पर ढह गया।

नगर निकाय अधिकारियों ने इस इमारत को ''खतरनाक'' घोषित किया था और परिसर में मरम्मत का काम चल रहा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों को मामला दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह घटना तब हुई जब इमारत की मरम्मत का काम चल रहा था।

॥ श्री संभवनाथाय नमः ॥
॥ श्री प्रेम-भुवनभानु-जयघोष-मणिप्रभ-राजेन्द्र--वरबोधि सूरीश्वरेभ्यो नमः ॥
श्री वेपेरी श्वे. मू. पू. जैन संघ, चेन्नई के तत्वावधान में
6 रविवारीय युवा शिबिर Divine Connection

Age Limit 15 से 55 साल तक के भाईओ एवं बहनों
Start From 02.08.2026 to 06.09.2026
Shibir Time MORNING 9.30 To 12.30

दिव्यकृपा : पू. युगप्रभावक आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरीश्वरजी म.
प्रवचनकार : पू. आचार्य श्री कुलबोधि सूरीश्वरजी म.

Reel Life के चक्कर में Real Life से दूर हो रही युवा पीढी के लिये इस DIVINE CONNECTION YUVA SHIBIR का आयोजन किया गया है।
हमारा आग्रहभरा अनुरोध है कि आप अपने फ्रेन्ड सर्कल के साथ इस युवा शिबिर में अवश्य पधारें।

1st 02 AUG. SUNDAY | 2026 Topic Life Management Sponser संघवी पंकुबाई भूरमलजी कोठारी वड़गांव / चेन्नई
2nd 09 AUG. SUNDAY | 2026 Topic Mind Management Sponser संघवी रमीलाबेन कमलेशकुमारजी लालचंदजी मंडवारीया / चेन्नई
3rd 16 AUG. SUNDAY | 2026 Topic Behaviour Management Sponser श्रीमती शांतिदेवी जवाहरमलजी चंदन सांचोर / चेन्नई
4th 23 AUG. SUNDAY | 2026 Topic Relation Management Sponser श्री हुलासचंदजी प्रमोदकुमारजी चोरड़िया नागौर / चेन्नई
5th 30 AUG. SUNDAY | 2026 Topic Religion Management Sponser KHAZANA JEWELLERY तखतगढ़ / चेन्नई
6th 06 SEP. SUNDAY | 2026 Topic This not, That not, Then what? Sponser संघवी पानीदेवी मोहनलालजी सोनवाड़िया मुथा मांडवला / चेन्नई

शिबिर स्थल : गौतम किरण नं. 39, ATKINSON ROAD, VEPERY.

सूचना
* रु. 100 देकर शिबिर पास वेपेरी जैन संघ की पेढ़ी में से प्राप्त कर लेवें।
* शिबिर में प्रातः 9.30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।
* भाईओं White & White में एवं महिलाएं Red & Red वस्त्र में पधारें।
* शिबिर पूर्णाहूति के पश्चात् साधर्मिक भक्ति (भोजन) का लाभ अवश्य देवें।

आयोजक : श्री वेपेरी श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ, 59, EVK, सम्पथ रोड, वेपेरी, चेन्नई.

ओडिशा के हीराकुड बांध से महानदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण हीराकुड बांध से महानदी में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसके चलते ओडिशा के 30 में से 20 जिलों में निचले इलाकों में पानी भर गया और करीब सात लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

महानदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण इसकी कई सहायक नदियां उफान पर हैं, जिससे स्थिति बिगड़ गई है। हालांकि, पिछले एक दिन बारिश नहीं होना राज्य के लिए राहत साबित हुआ है।

बाढ़ से सात लाख लोग प्रभावित

बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने वाले राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से भारी जल प्रवाह के कारण हीराकुड बांध के 14 गेट खोले गए हैं, जिससे दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। पहले सिर्फ दो गेट खुले थे।

मंत्री ने कहा, ''पानी को कटक के पास मुंडाली तक पहुंचने में लगभग 36 से 40 घंटे लगेंगे।'' शुक्रवार की सुबह तक, जलाशय में जल स्तर इसकी पूर्ण भंडारण क्षमता 630 फुट के मुकाबले 623.52 फुट था। बांध में प्रति सेकंड लगभग 3,69,322 क्यूसेक पानी आ रहा था, जबकि लगभग 65,543 क्यूसेक पानी नीचे की ओर छोड़ा जा रहा था। पुजारी ने कहा कि मुंडाली में आठ लाख क्यूसेक से अधिक पानी 36 घंटे के भीतर छोड़ा जाना चाहिए, जिससे हीराकुड से छोड़े जाने वाले अतिरिक्त पानी के लिए जगह बन सके। मंत्री ने कहा, ''यह एक बड़ी राहत है कि राज्य भर में और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों से बारिश नहीं हुई है।'' उन्होंने कहा कि कटक, पुरी, खुर्दा और जगतसिंहपुर जिलों के कुछ इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों की परेशानियां कम करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं।

पुजारी ने कहा कि राज्य उत्तरी और तटीय क्षेत्रों में 520 राहत केंद्र संचालित कर रहा है, जहां लगभग दो लाख लोगों के लिए तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 1.90 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। विशेष राहत आयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल ने कहा कि हालिया बाढ़ ने राज्य के 30 जिलों में से 20 में सात लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है।

देश में अब तक इबोला का कोई मामला नहीं, प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी बढ़ाई गई : नड्डा

नड्डा ने कहा कि सरकार ने इबोला प्रभावित देशों से यात्रियों के प्रवेश पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। प्रवेश बिंदुओं पर आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की पिछले 21 दिनों के दौरान प्रभावित देशों की यात्रा के इतिहास की जांच की जा रही है...

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किया कि 23 मई से अब तक इबोला प्रभावित देशों से भारत आने वाले 10,974 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की इस बीमारी के लिए जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश में अबतक इबोला बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा बुंदीबुग्यो इबोला के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किए जाने के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है। नड्डा ने कहा कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी), युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों की 23 मई से 28 जुलाई के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों द्वारा जमा किए गए स्व-घोषणा प्रपत्रों और एयर सुविधा 2.0' पोर्टल के माध्यम से जांच की गई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इबोला प्रभावित देशों से यात्रियों के प्रवेश पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रवेश बिंदुओं पर आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की पिछले 21 दिनों के दौरान प्रभावित देशों की यात्रा के इतिहास की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा बुंदीबुग्यो इबोला के प्रकोप को पीएचईआईसी घोषित करने और अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (अफ्रीका सीडीसी) द्वारा महाद्वीपीय सुरक्षा का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईसीएस) घोषित किए जाने के बाद उपायों को मजबूत किया गया।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य हितधारकों के समन्वय से तैयारी और निगरानी उपाय किए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर व्यापक स्क्रीनिंग और निगरानी की व्यवस्था की गई है, जबकि निगरानी, स्क्रीनिंग, पृथकवास, क्लीनिकल प्रबंधन, प्रयोगशाला परीक्षण, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण और मामले की रिपोर्टिंग को कवर करने वाले परामर्श और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को जारी की गई हैं।

गुजरात के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश

सूरत, खेड़ा और आणंद सबसे अधिक प्रभावित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात के मध्य और दक्षिण भागों के कई ज़िलों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई तथा सबसे ज़्यादा प्रभावित सूरत में 1,500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के बाद, 13 ज़िलों में बहुत ज़्यादा बारिश को लेकर 'रेड अलर्ट' और सात ज़िलों में भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है।

राज्य के राहत आयुक्त गौरव मकवाना ने एक बयान में कहा, नर्मदा, आणंद, खेड़ा, छोटा उदेपुर, वडोदरा और सूरत समेत कई जिलों में अच्छी-खासी बारिश हुई है तथा स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है।

राज्य आपात अभियान केंद्र के डेटा के अनुसार, शुक्रवार को सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक सूरत, खेड़ा, आणंद, भरूच और नर्मदा के कई तालुकों में 150 मिलीमीटर (मिमी) ज़्यादा बारिश हुई। सूरत सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है, जहां इस दौरान उमरपाड़ा तालुका में 247 मिमी बारिश दर्ज की गई। सूरत के निगम आयुक्त एम. नागराजन ने कहा, शुक्रवार को रेड अलर्ट के बीच, निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 1,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और भारतीय सेना की टीम तैयार रखी गयी हैं।''

खेड़ा ज़िले के नाडियाड में शुक्रवार को अपराह्न दो बजे तक आठ घंटों में 191 मिमी बारिश हुई, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। ज़िले के वासो इलाके में 177 मिमी बारिश हुई। नाडियाड में लोग घुटने तक भरे पानी में चलते हुए दिखे। आणंद ज़िले के बोरसद में सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक 170 मिमी बारिश हुई। खंभात में 165 मिमी बारिश दर्ज की गई। आठ घंटे में भरूच जिले के नेतरंग में 155 मिमी बारिश हुई, जबकि आणंद जिले के पेटलाड और नर्मदा जिले के सागबारा में 152 मिमी बारिश हुई। इस अवधि के दौरान तापी जिले के डोलवन में 149 मिमी बारिश हुई।

सूरत के अंबिका में 146 मिमी, नर्मदा के गरुड़ेश्वर में 144 मिमी, सूरत के अरेथ में 138 मिमी और डांग के सुबीर में 137 मिमी वर्षा हुई। शुक्रवार दोपहर से रेड अलर्ट के बीच अहमदाबाद के कई इलाकों में भी बारिश हुई। राहत आयुक्त मकवाना ने बताया कि गुजरात में बारिश से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 33 टीम तैनात की गई हैं।

'घाटकोपर हिट एंड रन' मामले में अदालत ने 17 वर्षीय आरोपी की जमानत रद्द की

मुंबई/भाषा। मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को घाटकोपर हिट-एंड-रन' मामले में 17 वर्षीय आरोपी को मिली जमानत रद्द कर दी। यह फैसला पीड़ित की पत्नी की याचिका पर लिया गया, जिन्होंने दुर्घटना के एक महीने बाद लड़के को रिहा किए जाने के निर्णय को चुनौती दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबुद्दीन शेख ने किशोर न्याय बोर्ड को निर्देश दिया कि वह नाबालिग को अपनी हिरासत में ले और उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश जारी करे।

यह घटना पांच फरवरी को विद्याविहार में सोमैया कॉलेज के पास हुई थी, जहां एक व्यापारी का नाबालिग बेटा कार चला रहा था और उसकी कार एक स्कूटर से टकरा गई थी। इस हादसे में स्कूटर सवार धुमिल पटेल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मीनल गंभीर रूप से घायल हो गईं।

प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ाई गई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने शुक्रवार को इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया अब 15 अगस्त तक जारी रहेगी। बयान में कहा गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है। मंत्रालय ने कहा कि ये पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं।

उसने कहा कि भारत में निवास करने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 31 जुलाई 2026 तक पांच वर्ष से 18 वर्ष के बीच है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। मंत्रालय ने कहा, स्व-नामांकन सहित किसी भी नागरिक द्वारा की गई सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी।

प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत का 90 वर्ष की आयु में निधन

भोपाल/भाषा। प्रसिद्ध साहित्यकार और 'पद्मश्री' से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का शुक्रवार को यहां 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पंत बीते कुछ समय से अस्वस्थ थे और शुक्रवार सुबह हृदयगति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनके बड़े भाई चंद्रशेखर पंत ने एक संदेश में कहा, शोकाकुल हृदय से सूचना है कि मेरे अनुज और प्रीति, निवेदिता व अदिति के पिता तथा हिंदी भवन भोपाल के पूर्व मंत्री-संचालक कैलाश चंद्र पंत 'दादा' का प्रभु-मिलन हो गया है। उन्होंने बताया कि कैलाश चंद्र पंत का अंतिम संस्कार शनिवार को भदभदा विश्राम घाट में किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैलाश चंद्र पंत के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मूल रूप से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के खंतोली गांव निवासी पंत का जन्म 26 अप्रैल 1936 को इंदौर के महू में हुआ था। उनके पिता लीलाधर पंत तथा माता हरिप्रिया पंत का परिवार रोजगार के सिलसिले में मध्यप्रदेश में बस गया था।

रमेश ने सभापति को भेजा प्रमाण, कहा: देवरस ने लिखा था इंदिरा को पत्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन को पत्र लिखकर उच्च सदन में उनके द्वारा किए गए उस दावे को सत्यापित करने के लिए प्रमाण उपलब्ध कराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के तत्कालीन सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस ने संघ पर लगा प्रतिबंध हटाने का आग्रह करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रमेश ने सभापति को लिखे पत्र के साथ देवरस द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों की प्रमाणित प्रतियां भी भेजीं। रमेश ने अपने पत्र में कहा, कल शाम मैंने संसदीय कार्य मंत्री के एक बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। भाजपा सांसदों ने मेरे उस दावे का प्रमाण मांगा था कि आरएसएस प्रमुख ने आपातकाल के समर्थन में इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था।''

उन्होंने कहा, ''मैं अभिलेख के लिए अपना सत्यापन संलग्न कर रहा हूं। इसमें इंदिरा गांधी को लिखे गए दो पत्र तथा आचार्य विनोबा भावे को लिखा गया एक पत्र शामिल है।'' रमेश ने ब्रह्म दत्त की पुस्तक फाइव हेडेड मॉन्स्टर : ए फैक्चुअल नैरेटिव ऑफ द जेनेसिस ऑफ जनता पार्टी' का भी हवाला दिया है। इस पुस्तक में वर्ष 1975 में पुणे की यरवदा केंद्रीय कारागार से देवरस द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए दो पत्रों का उल्लेख है। पुस्तक के अनुसार, इन पत्रों में देवरस ने इंदिरा गांधी से आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था और संघ के बारे में ''व्याप्त भ्रम'' दूर करने का प्रयास किया था। उन्होंने दावा किया था कि संघ देशभर में विकास कार्यों में लगा हुआ है।

पुस्तक में यह भी कहा गया है कि संघ का बिहार या गुजरात के किसी आंदोलन, जिसमें जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी शामिल है, से कोई संबंध नहीं था। रमेश के अनुसार, आचार्य विनोबा भावे को लिखे एक अन्य पत्र में देवरस ने उनसे आग्रह किया था कि वह प्रधानमंत्री के मन में संघ के बारे में बनी गलत धारणा दूर करें, ताकि संघ के स्वयंसेवकों को जेल से रिहा किया जा सके और वे देश के विकास कार्यों में भाग ले सकें।

पुस्तक में कहा गया है कि विनोबा भावे को यह पत्र मुंबई के सेंट जोसिस अस्पताल के जेल वार्ड से लिखा गया था।

अगर पति व्यभिचार का आरोप लगाता है, तो अदालत को पहले इस मुद्दे पर फैसला करना होगा : न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अगर पति व्यभिचार का आरोप लगाता है, तो अदालत को पत्नी को अंतरिम गुजरा भत्ता देने का फैसला सुनाने से पहले पहले उस आरोप पर निर्णय लेना होगा। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अदालतों का यह मानना त्रुटिपूर्ण होगा कि ऐसे आरोप पर निर्णय केवल सुनवाई के अंतिम चरण में ही किया जा सकता है। पीठ ने कहा, चूंकि, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125(4) में यह प्रावधान है कि अगर व्यभिचार का आरोप साबित हो जाता है, तो पत्नी न तो अंतरिम और न ही अंतिम गुजारा-भत्ता की हकदार होगी। इसलिए हमारा मत है कि अगर पति धारा 125(4) के तहत आवेदन करता है और शुरू में ही सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप साबित कर देता है, तो अंतरिम गुजारा-भत्ता पर रोक लगाई जा सकती है।

शीर्ष अदालत का यह फैसला एक व्यक्ति की अपील पर आया है। व्याभिचार के आधार पर गुजारा भत्ता का विरोध करने वाली व्यक्ति की याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसे चुनौती देते हुए उसने शीर्ष अदालत का रुख किया था। याचिकाकर्ता व्यक्ति और महिला का विवाह सात जुलाई 2014 को हुआ था। शादी के कुछ साल बाद ही उनके बीच परेशानियां शुरू हो गईं, जिसके कारण महिला ने कथित तौर पर पुरुष पर कई आरोप लगाए और पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराईं। आखिरकार, 13 मई 2020 को उसने अपने बच्चे और कीमती सामान के साथ ससुराल छोड़ दी।

बाद में महिला ने उदयपुर के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अंतरिम गुजारा-भत्ता के लिए अर्जी दी। इसके बाद व्यक्ति ने भी सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत अर्जी दाखिल की और दलील दी कि पत्नी के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण वह किसी भी तरह के अंतरिम गुजारा-भत्ता की हकदार नहीं है। हालांकि, अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित करने के लिए कि पत्नी विवाहेतर संबंध में रह रही थी, पति ने कई तस्वीरें और अन्य सबूत पेश किए हैं। सीआरपीसी की धारा 125(4) के अनुसार, अगर कोई पत्नी व्यभिचार में शामिल है, तो वह धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा-भत्ता, अंतरिम गुजारा-भत्ता या कानूनी खर्च का दावा नहीं कर सकती।

डॉक्टर हमला प्रकरण : पुलिस ने उच्च न्यायालय में दो सप्ताह में जांच पूरी करने का आश्वासन दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई। महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह ठाणे जिले के डोंबिवली में एक नगर निगम अस्पताल में चिकित्सकों के साथ मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे के खिलाफ जांच में तेजी लाएगी और इसे दो हफ्ते के अंदर पूरा कर लेगी। छह जुलाई को यह घटना हुई थी जिसके दो दिन बाद म्हात्रे को गिरफ्तार किया गया था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 14 जुलाई को म्हात्रे को जमानत दे दी लेकिन चार दिन बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए जमानत पर स्थगन लगा दिया। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार म्हात्रे ने प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया और अब वह न्यायिक हिरासत में हैं।

म्हात्रे के वकील आबाद पोंडा ने उच्च न्यायालय से गुज़ारिश की कि उनके मुवक्किल पर कड़ी शर्तें लगाकर उन्हें जेल से रिहा करने पर विचार किया जाए और वह जांच पूरी होने तक महाराष्ट्र से बाहर रहने को भी तैयार हैं। अदालत की मदद के लिए नियुक्त वरिष्ठ वकील अशोक मुंडार्गी और 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' की ओर से पेश हुए एस यू कामदार ने इसका विरोध किया । उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक म्हात्रे को ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने खंडपीठ को बताया कि पिछले हफ़्ते अदालत के आदेश के मुताबिक, जांच का काम अब पुलिस के उपायुक्त संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले दर्ज किए गए नौ लोगों के अलावा 17 और लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं तथा 10 और गवाहों के बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में तेज़ी लाने और इसे दो हफ़्ते के अंदर पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड़ की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले पर छह अगस्त को आगे सुनवाई करेगी तथा म्हात्रे की ज़मानत की अर्ज़ी पर विचार करेगी। कल्याण-डोंबिवली नगर निगम के शास्त्री नगर अस्पताल में दो चिकित्सकों एवं नर्सों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में छह जुलाई की रात को पार्षद और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना तब हुई जब एक परिवार को नवजात शिशु को दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई थी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था।

द्रमुक सांसद का दावा : 336 रेलवे अधिकारियों ने जनता के पैसे से लग्जरी ट्रेनों में यात्रा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। द्रमुक सांसद वी एस मथेश्वरन ने शुक्रवार को दावा किया कि रेल मंत्रालय ने पिछले 12 साल में 'पैलेस ऑन व्हील्स', 'महाराजा एक्सप्रेस' और 'डेक्कन ओडिसी' जैसी लग्जरी ट्रेनों में 336 रेलवे अधिकारियों की यात्रा पर जनता के करोड़ों रुपये बर्बाद किए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंत्रालय ने इस सवाल पर संसद को गुमराह किया कि क्या रेलवे अधिकारियों को भारतीय रेलवे सेवक (पास) नियम, 1986 के तहत लग्जरी ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति है।

मथेश्वरन ने पीटीआई-भाषा से कहा, 2022 में, मंत्रालय ने लोकसभा को बताया था कि रेलवे अधिकारी अपने परिवारों के साथ लग्जरी ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब, 29 जुलाई, 2026 को मेरे सवाल के जवाब में कहा गया कि वे ऐसी यात्रा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब मैंने मंत्रालय से ऐसे सभी अधिकारियों के नाम और पद बताने को कहा, तो उन्होंने सिर्फ एक संख्या (336) बताई, उन अधिकारियों के नाम नहीं।''

'पैलेस ऑन व्हील्स', 'महाराजा एक्सप्रेस' और 'डेक्कन ओडिसी' लग्जरी ट्रेनें हैं जिन्हें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) चलाता है। यात्रा के कार्यक्रम के आधार पर इनका किराया प्रति व्यक्ति 4.5 लाख रुपये से लेकर 26 लाख रुपये तक है। मथेश्वरन ने संसद में यह मुद्दा कई बार उठाया है। हाल ही में, 29 जुलाई को उन्होंने रेल मंत्रालय से भारतीय रेलवे सेवक (पास) नियम, 1986 के उस खास प्रावधान की जानकारी मांगी, जिसके तहत रेलवे अधिकारियों को आधिकारिक ड्यूटी के दौरान अपने परिवारों के साथ लग्जरी ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति है। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, ''रेलवे सेवक (पास) नियम, 1986 के अनुसार, रेलवे अधिकारियों को भारतीय रेलवे की ट्रेनों - जिनमें राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, हमसफर, गतिमान और वंदे भारत ट्रेनें शामिल हैं - में परिवार के साथ यात्रा करने की अनुमति है।'' मंत्रालय ने कहा, इसके अलावा, राज्य पर्यटन विकास निगमों और आईआरसीटीसी द्वारा संचालित लग्जरी/पर्यटक ट्रेनों के संबंध में रेल सेवक (पास) नियम, 1986 में कोई बदलाव नहीं किया गया है।'' मथेश्वरन ने इन लग्जरी ट्रेनों में यात्रा करने वाले अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2026 को बताया कि पिछले 12 साल में कुल 336 रेलवे अधिकारियों ने अपने ट्रैवल पास का इस्तेमाल करके इंडियन रेलवे की लग्जरी ट्रेनों में यात्रा की है। मथेश्वरन ने कहा कि मंत्रालय का 29 जुलाई का जवाब, 27 जुलाई, 2022 को लोकसभा में दिए उसके जवाब से अलग है।

जिंदा दफन सर्कस कलाकार की मौत, उस्ताद का लालच बना मौत का कारण

गुरुग्राम(हरियाणा)/भाषा। नूंह जिले में एक गड्ढे में तीन दिन तक जिंदा दफन रहने के दौरान दम घुटने से मरने वाले सर्कस कलाकार दीपक के दुखी परिवार का कहना है कि उसकी मौत किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसके उस्ताद के लालच का परिणाम थी। परिवार का एकमात्र सहारा दीपक की उम्र केवल 27 साल थी।

फरीदाबाद के गौंची गांव के रहने वाला दीपक पारंपरिक कलाकारों के परिवार से था, जो एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। हालांकि उसने कई बार जिंदा दफन होने का करतब दिखाया था जिसके तहत बोरी में बंद करके उसे जिंदा दफनाया जाता था और वह बाद में

बाहर निकलता था, लेकिन वह कभी 24 घंटे से अधिक समय तक अंदर नहीं रहा था। परिवार का कहना था कि दीपक के गुरु सतीश उर्फ पुलसिया ने 7,100 रुपये की पूरी रकम पाने के लिए उसे 72 घंटे तक गड्ढे में बंद रखा था। दीपक की भाभी सुनीता ने बताया कि हर कार्यक्रम में दर्शकों को यह बताया जाता था कि 7,100 रुपये जमा होने के बाद ही दीपक को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि, यह दावा सिर्फ लोगों को अधिक पैसे देने के लिए प्रोत्साहित करने की एक चाल थी। असल में चाहे कितनी भी रकम जमा हुई हो 24 घंटे पूरे होते ही दीपक को बाहर निकाल लिया जाता था। सुनीता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, इस बार 24 घंटे में 7,100 रुपये का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए पुलसिया ने जिंदा रहते हुए दफन रहने की अवधि को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया। जब तय समय के बाद भी दीपक को बाहर न निकालने पर ग्रामीणों ने विरोध किया, तो गड्ढे से मिट्टी हटाई गई। लेकिन तब तक दीपक की मौत हो चुकी थी।

कावेरी जल विवाद को लेकर न्यायालय जाएगी तमिलनाडु सरकार : मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के कानून मंत्री आर. निर्मल कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल में अपना निर्धारित हिस्सा हासिल करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। इस बीच, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से तीन अगस्त का अपना प्रस्तावित कर्नाटक दौरा रद्द करने का आग्रह किया।

निर्मल कुमार ने अंतरराज्यीय नदी विवाद पर कर्नाटक के रुख को खारिज करते हुए पत्रकारों से कहा, हमें कानूनी रूप से उच्चतम न्यायालय के माध्यम से आवश्यक पानी हासिल करना होगा।''

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार अपने किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाने को तैयार है। मंत्री ने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति द्वारा निश्चित मात्रा में पानी छोड़ने का स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद कर्नाटक लगातार ऐसा करने से इनकार करता रहा है।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य ने कई दशकों से तमिलनाडु को पानी नहीं देने के मुद्दे के इर्द-गिर्द अपनी राजनीति की है। कुमार ने कहा, कर्नाटक की राजनीति ही कावेरी मुद्दे पर आधारित है। पिछले 30, 40 या 100 वर्ष से उसका पूरा राजनीतिक रुख यही रहा है कि वह पानी नहीं देगा।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस विवाद को राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि अपने किसानों की जीवनरेखा के रूप में देखती है। मंत्री ने राज्य की आगे की रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विजय कानूनी विशेषज्ञों, अनुभवी अधिकारियों और विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की व्यापक कानूनी रणनीति और अंतिम फैसलों की एक सप्ताह के भीतर घोषणा किए जाने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी समाधान के लिए चार विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें उच्चतम न्यायालय का दोबारा रुख करना, नया जल विवाद अधिकरण गठित करने की मांग करना, दोनों राज्यों के बीच सीधी बातचीत और केंद्र सरकार पर हस्तक्षेप कर आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए दबाव बनाना शामिल है। कुमार ने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी की उस हालिया टिप्पणी की भी कड़ी आलोचना की जिसे लेकर तमिलनाडु में विवाद पैदा हो गया है। चौधरी ने संसद में कहा था कि कावेरी विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फरवरी 2018 के अंतिम फैसले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कर्नाटक को नदी पर मेकेदातु बांध जैसी कोई संरचना बनाने से पहले निचले तटवर्ती राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की मंजूरी या सहमति लेना जरूरी हो।

इस बीच, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने मुख्यमंत्री विजय से तीन अगस्त का प्रस्तावित कर्नाटक दौरा रद्द करने का आग्रह किया। रामदास ने एक बयान में कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश की खुली अवहेलना कर रहे राज्य से बातचीत करने पर तमिलनाडु के महत्वपूर्ण अधिकार कमजोर पड़ सकते हैं। रामदास ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार कानूनी दायित्व पूरा करने के बजाय स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रही है और तमिलनाडु के प्रति टकराव का रुख अपना रही है।

अन्नाद्रमुक प्रमुख ने कावेरी विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव ई. के. पलानीस्वामी ने कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी का पानी छोड़ने से इनकार किए जाने को लेकर तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार से कड़ा रुख अपनाने का आग्रह करते हुए शुक्रवार को मांग की कि तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य के नदी जल अधिकारों और कृषि हितों की रक्षा के लिए यह बैठक बुलायी जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह मांग भी की कि सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे को आगामी कृषि बजट में सहकारी कृषि ऋण पूरी तरह माफ करके पूरा करे।

पलानीस्वामी ने एक बयान में कहा, उच्चतम न्यायालय ने कावेरी नदी के पानी के तटवर्ती राज्यों के बीच बंटवारे को लेकर स्पष्ट फैसला दिया है। इसके अनुसार कर्नाटक को जून में तमिलनाडु के लिए 9.19 अरब घन फुट (टीएमसी) पानी छोड़ना था, लेकिन उसने केवल 2.91 अरब घन फुट पानी छोड़ा। जुलाई में 31.24 अरब घन फुट पानी छोड़ा जाना था लेकिन कर्नाटक ने इस महीने के लिए निर्धारित मात्रा में अब तक पानी नहीं छोड़ा है। अन्नाद्रमुक प्रमुख ने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक को अपने जलाशयों से 29 जुलाई से 15 दिन तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।

उन्होंने कहा, ''कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।'' पलानीस्वामी ने कहा, हालांकि, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय कर्नाटक में सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा की है।'' उन्होंने कहा, ''शिवकुमार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय बातचीत के लिए बेंगलूरु आते हैं तो वह उन्हें हेलीकॉप्टर से कर्नाटक के जलाशयों का निरीक्षण कराएंगे।''

पलानीस्वामी ने दावा किया, इन परिस्थितियों में अगर कावेरी नदी पर मेकेदातु में बांध बनाया जाता है तो तमिलनाडु को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। पेयजल के लिए इस नदी पर निर्भर 20 से अधिक जिलों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा और डेल्टा क्षेत्र के जिले रेगिस्तान में बदल जाएंगे।'' उन्होंने मेकेदातु परियोजना पर केंद्र के इस जवाब को लेकर मुख्यमंत्री विजय की लगातार चुप्पी'' की कड़ी निंदा की कि जलाशय के निर्माण के लिए तटवर्ती राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। उन्होंने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना करने'' के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री की भी कड़ी आलोचना की। पलानीस्वामी ने कहा, मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य के किसानों की जीवनरेखा कावेरी नदी की रक्षा और मेकेदातु परियोजना को रोकने के उपायों पर चर्चा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाए।''

पलानीस्वामी ने आगामी कृषि बजट में सहकारी कृषि ऋण पूरी तरह माफ किए जाने की मांग की और कहा कि टीवीके ने 2026 के चुनाव में पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के सहकारी कृषि ऋण पूरी तरह माफ करने और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों के ऋण में 50 प्रतिशत की छूट देने का वादा किया था। उन्होंने कहा, सत्ता में आने के बाद सरकार ने 75,000 रुपये तक का ऋण लेने वाले सीमांत और छोटे किसानों के लिए ही पूरा ऋण माफ करने की घोषणा करके नाटक किया, जबकि इससे अधिक बकाया वाले किसानों को मिलने वाली राहत केवल 35,000 रुपये तक सीमित कर दी।'' उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु के किसान इस भ्रामक'' घोषणा के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

पलानीस्वामी ने कहा, ''टीवीके सरकार को छह अगस्त 2026 को कृषि बजट पेश करते समय अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार सभी सहकारी कृषि ऋण पूरी तरह माफ करने की घोषणा करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अन्नाद्रमुक सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ राज्यव्यापी व्यापक आंदोलन शुरू करेगी।''

कावेरी विवाद सुलझाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कर्तव्य : तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष बी. मणिकम टैगोर ने शुक्रवार को पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास पर कावेरी जल विवाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घसीटने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की। टैगोर ने कहा कि राज्यों के बीच के इस मुद्दे को सुलझाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बुनियादी कर्तव्य और ज़िम्मेदारी है। लोकसभा सदस्य टैगोर ने एक बयान में अंबुमणि के हालिया बयान का जवाब दिया।

अंबुमणि ने राहुल गांधी को उनकी एक अगस्त की चेन्नई यात्रा से पहले कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का विरोध करने की चुनौती दी थी। टैगोर ने दावा किया, अंबुमणि ने घोषणा की थी कि अगर राहुल गांधी जलाशय के निर्माण का विरोध करते हैं, तो पीएमके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से बाहर निकलने के लिए तैयार रहेगी। अंबुमणि के बयान को गैर-जरूरी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए, टैगोर ने कहा कि पानी छोड़ने के आदेश को लागू करने की पूरी ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

उन्होंने कहा, ''इस साल कम बारिश की वजह से तमिलनाडु को कावेरी का तय हिस्सा नहीं मिल पाया है।'' उन्होंने बताया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक रोज़ाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। टैगोर ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करना और प्राधिकरण के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री मोदी का कर्तव्य है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री इस कर्तव्य को निभाने में विफल हो रहे हैं।

न्यायालय ने तमिलनाडु धोखाधड़ी मामले में कार्यवाही रद्द की, आरोप दीवानी प्रकृति के बताए

नई दिल्ली/चेन्नई। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को चेन्नई में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में कार्यवाही रद्द कर दी और कहा कि आरोप पक्षकारों के बीच पूरी तरह से दीवानी विवाद की ओर इशारा करते हैं।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता ने पूरी तरह से दीवानी विवाद को 'फौजदारी रंग' देने की कोशिश की है, और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा।

उच्चतम न्यायालय ने दो अपीलकर्ताओं की अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मार्च 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपील करने वालों के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में लंबित कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अपील करने वालों पर आरोप है कि उन्होंने पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दंडनीय अपराध किए हैं। उच्चतम न्यायालय के पिछले एक फैसले का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा कि यह माना गया था कि एक ही तरह के आरोपों पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध नहीं चल सकते।

उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के नये मामले में सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता एवं पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को राहत देते हुए शुक्रवार को उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के एक नये मामले में अगले आदेश तक अग्रिम जमानत दे दी। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ बालाजी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। पीठ ने जो शर्तें लगाई हैं उसके तहत बालाजी जांच में सहयोग करेंगे, अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे और किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।

न्यायमूर्ति बागची ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्णकुमार से कहा, जमानत की शर्तों का तनिक भी उल्लंघन हो तो आप तुरंत हमारे पास आइए। हम अपने आदेश में बदलाव कर देंगे या उसे रद्द कर देंगे।'' इससे पहले दिन में न्यायमूर्ति वी. मोहना ने बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टासमैक) में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के नये मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाली बालाजी की याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सहमति जताई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने टासमैक घोटाला मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दर्ज प्राथमिकी में बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी थी। इसके तुरंत बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं --कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अमित आनंद तिवारी-- ने द्रमुक नेता की ओर से न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि बालाजी के खिलाफ किसी भी समय दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश ने कृष्णकुमार से पूछा कि बालाजी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत क्यों है, क्योंकि यह मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है।

वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया कि आरोप 2021-25 की घटना से जुड़े हैं और बालाजी ने प्राथमिकी दर्ज होने से रोका था क्योंकि वे उस समय मंत्री थे, इसलिए उन्हें अदालत से पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल सकती। बालाजी की ओर से वरिष्ठ वकीलों, मुकुल रोहतगी और अमित आनंद तिवारी, के साथ सिब्बल पेश हुए और कहा कि यह एक अजीब मामला' है, क्योंकि प्राथमिकी 28 जुलाई को तब दर्ज की गई जब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई टीवीके सरकार सत्ता में आई। यह प्राथमिकी एक दूसरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर हलफनामे पर आधारित थी। उन्होंने कहा, जिन घटनाओं की बात हो रही है, वे 2021-25 के दौरान की हैं। ईडी ने 2025 में इस अदालत में एक हलफनामा दायर किया था। जिस व्यक्ति ने हलफनामा दायर किया था, वह अब बदल गया है, क्योंकि नई सरकार बन गई है। उसी हलफनामे के आधार पर 28 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इसके बाद न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि वह अब मंत्री नहीं हैं और राज्य सरकार उनके प्रभाव में नहीं है, लेकिन न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि वह जांच से भागें नहीं और गवाहों को प्रभावित न करें। कृष्णकुमार ने यह भी कहा कि यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है और इसमें अग्रिम ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यदि मामले की जांच के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो, तो राज्य सरकार अदालत से अनुमति मांग सकती है। बालाजी तमिलनाडु विधानसभा में कोयंबटूर दक्षिण सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

घोड़े के खेत में चरने पर हुए विवाद में किसान की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोडाइकनाल। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पास स्थित पहाड़ी गांव पूमबारई में खेत में पशु चराने को लेकर जारी विवाद में 26 वर्षीय युवक की हत्या के बाद शुक्रवार को तनाव बढ़ गया। घटना में 24 वर्षीय एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था।

स्थानीय लोगों ने घटना में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूमबारई में कृषि लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है।

पिछले कुछ महीनों से स्थानीय किसान रघु और रामर के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि रामर का घोड़ा बार-बार रघु के खेत में चरने चला जाता था।

सूत्रों ने बताया कि यह विवाद उस समय हिंसक संघर्ष में बदल गया जब रघु ने रामर (26) और उसके साथी प्रशांत (24) को पूमबारई के पास एक खेत में बुलाया। वहां हुई बहस के दौरान रघु ने दरांती से दोनों पर हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि हमले में रामर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल प्रशांत को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार, आरोपी और दोनों पीड़ित अलग-अलग समुदायों से हैं, जिसके कारण घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया।

वंदे मातरम के 150 साल

लोक भवन ने निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु लोक भवन ने शुक्रवार को 'वंदे मातरम' गीत के लिखे जाने के 150 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित राज्य-स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। लोक भवन की एक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतियोगिता का मकसद युवाओं में राष्ट्र गीत के भावनात्मक, ऐतिहासिक और समकालीन महत्व के बारे में समझ को गहरा करना था।

लोक भवन की विज्ञप्ति में बताया गया है कि तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित स्कूली स्तरों की दो व विश्वविद्यालय स्तर की एक प्रतियोगिता में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। स्कूल के छात्रों ने भारत की आजादी की लड़ाई में इस गाने की अहम भूमिका और देश में जोश भरने की इसकी भावना पर आधारित विषयों पर निबंध लिखे। वहीं, कॉलेज के प्रतिभागियों ने 'विकसित भारत 2047' के निर्माण में इस गाने की आज के समय में अहमियत पर बात की। विशेषज्ञों की एक टीम ने सभी श्रेणी में सबसे अच्छे निबंध चुने। राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों के विचारपूर्ण निबंधों की तारीफ की। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विजेताओं को क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 25,000 रुपये का नकद इनाम और आधिकारिक प्रशस्ति-पत्र दिए जाएंगे। विशेष पुरस्कार पाने वालों को भी प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल 15 अगस्त, 2026 को चेन्नई के लोक भवन में ''स्वतंत्रता दिवस के ऐट होम'' समारोह के दौरान विजेताओं के माता-पिता और संस्थान के प्रमुखों की मौजूदगी में खुद उन्हें (विजेताओं को) पुरस्कार देंगे।

आईआईटी मद्रास के एआई आधारित सड़क सुरक्षा हैकाथॉन में शामिल हुए बिम्सटेक देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित किया। आईआईटी मद्रास ने शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्र ने इसके तहत बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के लिए एक विशेष श्रेणी शुरू की। इसमें भारत के साथ-साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के विद्यार्थी, इंजीनियर, शोधकर्ता और विशेषज्ञ शामिल हुए।

इसका उद्देश्य 'ग्लोबल साउथ' के लिए सबसे बड़ा हैकाथॉन आयोजित करना था। ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य मुख्य रूप से विकासशील, अल्प विकसित और कम आय वाले देशों के समूह से है। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। इस आयोजन के जरिये आईआईटी मद्रास ने सड़क सुरक्षा जैसी साझा एवं गंभीर समस्या के समाधान के लिए सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सहयोग का साझा माध्यम बनाया गया। बिम्सटेक एआई सड़क सुरक्षा हैकाथॉन 2026' सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में आईआईटी मद्रास परिसर में सड़क सुरक्षा में एआई' विषय पर आयोजित किया गया। इस पहल की घोषणा आईआईटी मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र ने फरवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में की थी। बिम्सटेक क्षेत्र में करीब 1.8 अरब लोग रहते हैं और यहां हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग दो लाख लोगों की मौत होती है। इससे पूरे क्षेत्र में सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए आंकड़ों और प्रौद्योगिकी पर आधारित समाधान विकसित करने की तत्काल आवश्यकता रेखांकित होती है। आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि ने हैकाथॉन के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा, सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से हमारा संस्थान भारत और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक से निपटने के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नीति को एक साथ लाने में सफल रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई (दक्षिण)
38 & 39, व्हाइट्स रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014
पट्टे पर परिसर की आवश्यकता
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मद्दुरन्थकाम चेंगलपट्टु में हमारी प्रस्तावित शाखा के लिए 1400 वर्ग फीट ± 10% कारपेट एरिया वाला परिसर चाहिए जो अधिमानत रूप से भू-तल पर हो या हमारे विनिर्देशों के अनुसार किराए के लिए निर्माणाधीन हो, जिसका आगे का भाग अच्छा हो, मुख्य सड़क की ओर हो और जिसमें पर्याप्त पार्किंग हो।
संभावित आवेदक जिनके पास स्पष्ट स्वामित्व हो या मालिकों की ओर से बातचीत करने का अधिकार हो, वे बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.bank.in और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eprocure.gov.in से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई दक्षिण, व्हाइट्स रोड चेन्नई से कार्यालय अवधि के दौरान दिनांक 01.08.2026 से प्रारूप प्राप्त करें और अपनी तकनीकी बोली एंव मूल्य बोली प्रस्ताव को दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में तकनीकी बोली एंव मूल्य बोली लिखकर दिनांक 21.08.2026 को या उससे पूर्व अपराह्न 03:30 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई दक्षिण में जमा कर दें । तकनीकी बोली दिनांक 21.08.2026 को अपराह्न 04:30 बजे उपर्युक्त पते पर आवेदकों/ उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
कृपया कोई दलाल या बिचौलिया न आएं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी / अर्ध-सरकारी निकायों द्वारा पट्टे पर दी जाने वाली संपत्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। बैंक बिना कोई भी कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
दिनांक: 01.08.2026 क्षेत्र प्रमुख
जगह: चेन्नई

उत्तर पश्चिम रेलवे
निविदा संख्या-उपरे-एस सी-बी के एन-02-2026-27 ईपीसी दिनांक 14.07.2026 का
प्रथम शुद्धि पत्र
निविदा सूचना संख्या NWR-SC-BKN-02-2026-27-EPC दिनांक 14.07.2026 जो "उत्तर पश्चिम रेल्वे के बीकानेर रेलवे स्टेशन का ईपीसी मोड पर प्रमुख उन्नयन का कार्य" के कार्य के लिए है, के निविदा दस्तावेज में कई बदलाव किए गए हैं और जरूरी संशोधन (corrigendum) IREPS वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। संशोधनों की पूरी जानकारी IREPS वेबसाइट पर देखी जा सकती है। सभी बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे अपना ऑफर जमा करने से पहले सुधार (corrigendum) को जरूर देख लें।
संख्या – उपरे – एस सी –बी के एन –02–2026–27– ईपीसी दिनांक 29.07.2026
1110-CQ/26 उप मुख्य अभियंता / निर्माण, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

दक्षिण पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना सं. 18 UBL 2026-27, दिनांक: 28.07.2026
भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार ई-नीलामी / ई-निविदा हेतु निविदादाताओं को आमंत्रित करते हैं:

क्र.सं.	विवरण संक्षेप में	अनुमानित लागत
1	हुबली मंडल: उप कार्य-1: सहायक मंडलीय इंजीनियर/विजयपुरा (बीजेपी) उप मंडल में बादामी - होटगी (बीडीएम-एचजी) पर 41 नं. एलसी गेटों के लिए 24 महिने तक प्राईवेट एजेन्सी से पीवीसी टंकियों मे पंप करने के साथ पेय जल का संचार। उप कार्य-2: हुबली मंडल: सहायक मंडलीय इंजीनियर/विजयपुरा (बीजेपी) क्षेत्राधिकार पर 24 महीने की अवधि के लिए लेवेल क्रॉसिंग गेटों और गैंग यूनिट के लिए पानी का आपूर्ति।	रु. 42,13,991.00
2	हुबली मंडल: हुबली-गदग (यूबीएल-जेडीजी) खंड: कुसुगल (केयूजी) डिपो के लिए बैरिकेडिंग।	रु. 18,86,039.00
3	हुबली मंडल: गदग - होटगी (जीडीजी-एचजी) खंड: आलमट्टी - वंडाल (एलएमटी-डब्ल्यूडीएल) स्टेशनों पर क्रमानुसार किमी. 135/500-600 पर एलसी नं. 58 के बदले नियमित ऊंचाई सबवे का निर्माण कार्य।	रु. 8,42,20,970.00

निविदाओं जमा करने की अंतिम तिथि: 25.08.2026, 11:00 बजे तक
विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में
PUB/344/AAMG/PRB/SWR/2026-27 वरिष्ठ विभागीय इंजीनियर / समन्वय / हुबली
आसान टिकट बुकिंग, PNR स्थिति और दूसरी रेलवे सेवाओं के लिए RailOne ऐप डाउनलोड करें।
South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRAILWAYHQ | sw_railways

मजबूत फैसलों से हो रहा युवाओं और किसानों का कल्याण : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान शौर्य और पराक्रम की भूमि होने के साथ ही आस्था और विश्वास की पावन धरती है। यहां पग-पग पर आस्था धाम हैं तथा कई महापुरुषों ने अपने अलौकिक चमत्कारों से लोकहितकारी कार्य किए हैं। ओम बन्ना के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। वे उन्हें सड़क दुर्घटनाओं से रक्षा करने तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रद्धापूर्वक पूजते हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को ओम बन्ना मंदिर के लिए भूमि आवंटन के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाली जिले के चोटीला में ओम बन्ना मंदिर के विस्तार और सुव्यवस्थित विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है। इससे मंदिर परिसर का अच्छा विकास होगा और धार्मिक पर्यटन को भी गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी-विरासत भी' के मंत्र को आत्मसात कर प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। हमने ढाई वर्ष में विरासत स्थलों और आस्था धामों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राजस्थान में पृथ्वीराज चैहान, मीरा बाई, राणा सांगा, हाड़ी रानी और वीर शिरोमणि राव चंद्रसेन जैसे अनेक पैनोरमाओं का निर्माण कार्य करवाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में धार्मिक पर्यटन को नई गति देने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पुष्कर, खाटूश्यामजी, नाथद्वारा, केशोरायपाटन, डीग और चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक शहरों में हेरिटेज वॉक वे का निर्माण करवाएंगे। इसी प्रकार, किराडू के मंदिर समूह के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य होंगे। शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण के लिए भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाली के करूणामूर्ति धाम, ब्यावर के मकरमंडी माताजी मंदिर में विकास कार्य कराए जाएंगे। वहीं, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 1 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवा चुकी है। इस वर्ष भी हजारों वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से नेपाल के पशुपतिनाथ और एसी ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे। साथ ही, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवस्थान विभाग के अधीन खाली भूमि पर धर्मशालाओं के निर्माण एवं संचालन के लिए नई नीति बनाई जाएगी। इसी प्रकार, दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों पर मंदिरों में विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि जहां आस्था का सम्मान होता है, वहां संस्कृति सशक्त होती है, समाज संगठित होता है और विकास को नई दिशा मिलती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजते हुए विकसित, समृद्ध और गौरवशाली राजस्थान बनाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पानी एवं बिजली के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतार रही है, जिससे इनकी पर्याप्त उपलब्धता बढ़ रही है। मजबूत फैसलों से पेपरलीक पर लगाम लगाई है तथा युवाओं के लिए रिकॉर्ड भर्तियों से लेकर स्वरोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए भी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत सहित ओम बन्ना मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, मारवाड़ राजपूत सभा के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शुरू किया अनशन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े एनएसयूआई के तीन कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार से आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग पर पक्का आश्वासन नहीं देती, वे सिर्फ़ पानी पीकर रहेंगे। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) से जुड़े विजयपाल कुड़ी, वियोना जाट और कोशेन खान बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे गांधी नगर रेलवे स्टेशन इलाके में टोंक फाटक पुल के पास पानी की टंकी पर चढ़े थे और तब से वहीं हैं।

विजयपाल कुड़ी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उनके पास लगभग पांच लीटर पानी है। कुड़ी ने कहा, अब हमारे पास खाना नहीं है। हम अपने साथ कुछ खाना और एक रस्सी लाए थे ताकि जरूरत पड़ने पर नीचे से खाना ऊपर खींचा जा सके। लेकिन अब हमने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है और सिर्फ़ पानी पिएंगे।

उन्होंने बताया कि कल रात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे बातचीत की और भरोसा दिलाया कि वे उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक की व्यवस्था करेंगे। कुड़ी ने कहा, हमने उनसे कहा कि हमें ठोस पहल चाहिए। जब तक सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल करने का पक्का आश्वासन नहीं देती हम नीचे नहीं आएंगे। टंकी के ऊपर के हालात के बारे में बताते हुए कुड़ी ने कहा कि व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से प्रदर्शनकारी अपना खाना और पानी बचाकर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम थोड़े पानी और खाने के साथ टंकी पर चढ़े थे। निवृत्त होने की चुनौतियों को देखते हुए हमने कम खाया-पिया।'

गांधी नगर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) नारायण बाजिया ने कल रात इन आंदोलनाकरियों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि छात्रों को नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा, ''हम छात्रों के संपर्क में हैं और उन्हें नीचे आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बीच, एनएसयूआई के प्रवक्ता रमेश भाटी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों से कोई सार्थक बातचीत शुरू नहीं किए जाने के कारण शुक्रवार को भूख हड़ताल शुरू की गई। कांग्रेस संबद्ध इस संगठन के कार्यकर्ता राज्य में छात्र संघ चुनाव दुबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ये चुनाव कुछ साल से नहीं हुए हैं।

मानसून अभी सक्रिय रहेगा, कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में मानसून की सक्रियता फिलहाल बनी रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर संभाग तथा आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने का अनुमान है। विशेष रूप से जोधपुर संभाग के दक्षिणी हिस्सों में 31 जुलाई से दो अगस्त के बीच कहीं-कहीं भारी से अतिभारी वर्षा हो सकती है।

उधर, शुक्रवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि बांसवाड़ा जिले में भारी वर्षा हुई। इस अवधि में सबसे अधिक 69 मिलीमीटर वर्षा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में दर्ज की गई।

जनजातीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा नामांकन के लिए अधिकाधिक प्रयास हों : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास का आह्वान करते हुए शुक्रवार को कहा कि शिक्षा जितनी गुणवत्तापूर्ण और समयानुकूल होगी, उतनी ही वह जीवन के लिए उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगी। राज्यपाल बांसवाड़ा स्थित गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में नवनिर्मित शैक्षणिक भवन, कुलपति आवास और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का ऑनलाइन माध्यम से अनावरण कर रहे थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा जितनी गुणवत्तापूर्ण और समयानुकूल होगी, उतनी ही वह जीवन के लिए उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के नामांकन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाने पर बल दिया।

उन्होंने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उनका शिक्षा-दर्शन विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और सर्वांगीण विकास पर आधारित है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने का भी आग्रह किया।

राज्यपाल ने नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान को नशामुक्त बनाने के लिए स्थानीय समुदाय के साथ सतत संवाद और जनजागरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन का वास्तविक संरक्षक है, ऐसे में इस दृष्टि से विश्वविद्यालय को जनजातीय समुदाय की जल संरक्षण और प्रकृति संरक्षण संबंधी पारंपरिक ज्ञान-परंपराओं पर अधिकाधिक शोध और अनुसंधान करना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बागड़े ने कहा कि इसमें 'लोकल से ग्लोबल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा के अंतर्गत स्थानीय संसाधनों पर आधारित तकनीकों के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे ऐसी शिक्षा का प्रसार करें, जिससे विद्यार्थी अपनी क्षमता को पहचान सकें और आत्मनिर्भर बनने का सामर्थ्य विकसित कर सकें। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।

जिला कलेक्टर बनाए गए नोडल अधिकारी : श्रीनिवास

जयपुर। उच्चतम न्यायालय के आदेशों और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुपालन में राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सुदृढ़, आधुनिक एवं पारदर्शी करने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में की विस्तृत चर्चा। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के सभी दिशा-निर्देशों का समयबद्ध एवं पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित विभागों को अंतर-विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

वी श्रीनिवास ने कहा कि अवैध

बालू खनन की रोकथाम, समन्वय और निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन के नेटवर्क को ध्वस्त करने, वित्तीय पोषण करने वालों, परिवहनकर्ताओं और आपराधिक सिंडिकेट्स की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

उन्होंने कहा कि संरक्षण उपायों को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक एआई-एनालिटिक्स आधारित एक इंटेलिजेंट ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार करने के निर्देश। शुष्क मौसम के दौरान उच्च-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेज और ड्रोन सर्वे के जरिए नदी के स्वरूप में बदलाव और नए खनन स्थलों की मासिक मैपिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्य मार्गों और पुलों पर सीसीटीवी, पीटीजेड एवं एआई-सक्षम थर्मल कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर समन्वय बढ़ाने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर द्वार एक एसओपी जारी की जाएगी। साथ ही उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार, पुलिस और वन अधिकारियों की संयुक्त टीमें प्रत्येक 15 दिन में आकस्मिक निरीक्षण करेंगी।

लोकसेवकों में नागरिकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ाने वाली हो प्रशिक्षण व्यवस्था : मुख्य सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था की गुणवत्ता लोकसेवकों की क्षमता, कार्यकुशलता और दृष्टिकोण पर काफी हद तक निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केवल सेवा की औपचारिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षु अधिकारियों को तैयार करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक व्यवहारिक, समकालीन एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए ताकि अधिकारी बदलती प्रशासनिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करते हुए सुशासन को और सुदृढ़ बना सकें। मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रशिक्षण विभाग एवं हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण अवसंरचना तथा भावी कार्ययोजना के विषय में चर्चा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों के लिए मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाए। साथ ही विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिनसे उनकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता का निरंतर विकास हो।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में तकनीक का प्रभावी उपयोग समय की आवश्यकता है, इसलिए प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण एवं डिजिटल शिक्षण को व्यापक रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने प्रशिक्षण अवसंरचना के आधुनिकीकरण, आधुनिक कक्षाओं के विकास तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण वातावरण विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही, संस्थान को श्रेष्ठ प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शोध, प्रकाशनों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान को और अधिक प्रोत्साहित करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि संस्थान द्वारा मिशन कर्मयोगी एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एचसीएम रीपा ने प्रशासनिक प्रशिक्षण में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि संस्थान को सुशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को निरंतर अपनाते हुए प्रशासनिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ाना चाहिए।

बैठक में हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की महानिदेशक एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) श्रीमती श्रेया गुहा ने संस्थान की विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों एवं मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत संचालित पहलों की जानकारी दी। उन्होंने साधना सप्ताह जैसे सतत सीखने के अभियानों तथा यूएनएनएटीआई पोर्टल के प्रभावी उपयोग के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों के बीच संसाधनों, पाठ्य सामग्री एवं विशेषज्ञता के बेहतर आदान-प्रदान के संबंध में भी विस्तार से अवगत कराया।

विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त से

जयपुर। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।देवनानी ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी है।उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और व्यवस्थागत तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही 20 अगस्त, बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी।

सड़क हादसे में सेना के मेजर की मौत

जैसलमेर। जैसलमेर जिले में बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में सेना के एक मेजर की मौत हो गई जबकि दो लेफ्टिनेंट गंभीर घायल हुए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह हादसा शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर थईयात सेना क्षेत्र में हुआ। सदर पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार मेजर हमजा आरिफ (26) और उनके साथ दो अन्य सैन्यकर्मी सैन्य अड्डे से लौट रहे थे। अचानक सामने ऊंट आने से उनका वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। ऊंट से टकराने के बाद उनका वाहन लगभग 100 मीटर तक घिसटता चला गया।घायलों को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया।

राजस्थान पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए जारी किए विशेष दिशा-निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने हरिद्वार आने-जाने वाले कांवड़ियों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को यात्रा के दौरान सतर्कता, आपसी समन्वय और प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) वी.के. सिंह ने सभी संबंधित जिला पुलिस अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान बेहतर समन्वय, सतर्कता और प्रभावी पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं।

वी.के. सिंह ने कहा कि राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु 30 जुलाई से 11 अगस्त तक हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गृहनगर की ओर लौटेंगे। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान अपना मूल एवं वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखें। साथ ही उन्हें केवल निर्धारित पारंपरिक कांवड़ मार्गों और वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उपायुक्तों को जमीनी स्तर पर प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए हैं जिसके तहत किसी भी घटना की सूचना मिलने पर निकटतम पुलिस दल को 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी अथवा पुराने वीडियो और अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अचानक और पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, मिश्रित एवं संवेदनशील क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा गुजरने के दौरान भवनों की छतों पर पुलिस बल तैनात रहेगा तथा संपूर्ण मार्ग की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

आंकड़ों का क्रॉस वेरिफिकेशन कर पात्रों तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ : मुख्य सचिव

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर, जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा, पोषण एवं आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं पालनहार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के लगभग एक करोड़ परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं पालनहार योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य के सभी पेंशनरों के आंकड़ों का समुचित विश्लेषण करने हेतु प्रभावी डेटा डैशबोर्ड विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित मॉनिटरिंग से योजनाओं का संचालन अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

मुख्य सचिव ने जिला-वार पेंशनरों के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आंकड़ों का क्रॉस वेरिफिकेशन कर वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेंशन स्वीकृति एवं वितरण में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर किया जाएं।

भारत राष्ट्र महान, मेरा देश कमजोर ना हो : देवनानी

जयपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को उदयपुर के मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित युवा एवं आन्तरिक सुरक्षा विषयक मोहन लाल सुखाडिया स्मृति व्याख्यान माला का विधान सभा से वर्चुअल शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि भारत राष्ट्र महान है। इसकी एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता व संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी युवाओं की है। युवा देश का भविष्य के साथ वर्तमान भी है। युवाओं का सही दिशा में चलना राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। देवनानी ने कहा कि बदलते दौर में राष्ट्र की बाहरी सुरक्षा के साथ आन्तरिक सुरक्षा अधिक चुनौतिपूर्ण बनती जा रही है। मेरा देश कमजोर न हो, यह भाव सभी युवाओं के मन, मस्तिष्क में होना चाहिए।

देवनानी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सुखाडिया की जयन्ती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि वे राजस्थान के शिल्पी थे। लम्बे समय तक वे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। देवनानी ने युवा एवं आन्तरिक सुरक्षा विषय को वर्तमान सन्दर्भ में सामयिक और महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वर्तमान में युवाओं को साइबर सुरक्षा के योद्धा बनने की आवश्यकता है।

देवनानी ने कहा कि युवा यदि सही दिशा में चलता है तो राष्ट्र को शिखर तक ले जा सकता है। वही युवा भ्रम, भटकाव, असन्तोष, नकारात्मकता और विखण्डन के जाल में फंस जाए तो युवा शक्ति राष्ट्र के लिए चुनौती बन जाती है। उन्होंने कहा कि यदि युवा सजग है, उत्तरदायी है, समाज में विश्वास है तो आन्तरिक सुरक्षा अपने आप मजबूत होती जाती है।

भाजपा ने पाकिस्तान पर पीओजेके में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/श्रीनगर/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है तथा पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय तथा जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से इन कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉ. ताहिर चौधरी ने यहां प्रेसवार्ता में कहा, पीओजेके में हालात काफी खराब हो गए हैं। महिलाओं और बच्चों समेत बेगुनाह नागरिकों को (पाकिस्तान के सुरक्षाबलों द्वारा) कथित रूप से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व और संगठन इस पर खामोश हैं।''

इस प्रेसवार्ता में चौधरी के साथ पार्टी के दूसरे प्रवक्ता डॉ. अभिजीत सिंह जसरोटिया भी थे। चौधरी ने आरोप लगाया कि पीओजेके से सामने आ रहे वीडियो में वहां के लोग अंतरराष्ट्रीय दखल की अपील कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और कांग्रेस समेत क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इन कथित घटनाओं की निंदा क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा, मैं इन पार्टियों के नेताओं से पूछता हूं कि वे पीओजेके के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं।

जसरोटिया ने मीरपुर में 1947 के संघर्ष से जुड़ी घटनाओं को याद करते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के दौरान कई आम नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ा । उन्होंने संघर्ष से जुड़े फैसलों को लेकर उस समय के राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना की। हाल की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि पीओजेके में आम नागरिक निहत्थे होने के बावजूद हिंसा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने हाल में एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता को गोली मार दी। श्रीनगर से प्राप्त समाचार के अनुसार कश्मीर के धार्मिक गुरू मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ ने शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर हालात पर चिंता जताई तथा बातचीत करने एवं अधिकारों का सम्मान करने की अपील की। फारूक़ ने श्रीनगर में जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज, जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हमारी भावनाएं नियंत्रण रेखा के उस पार रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों के साथ हैं। पिछले डेढ़ महीने से जारी अशांति और कीमती जानें जाने की दुखद घटनाओं से हमें गहरा दुख पहुंचा है।

अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान-चढ़ावे की निगरानी सख्त हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अयोध्या/भाषा। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने श्रद्धालुओं के दान-चढ़ावे की निगरानी सख्त कर दी है तथा संग्रह के हर चरण और गिनती की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। न्यास के महंत दिनेन्द्र दास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

दास ने बताया कि 25 जुलाई से नई व्यवस्था लागू की गई है जिसमें दान के रखरखाव की पूरी शृंखला – दान पेटियों को खाली करने से लेकर गणना कक्ष तक में गिनती और आगे की प्रक्रिया सतत कैमरे की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आठ सदस्यीय निगरानी टीम तैनात की गई है और हर जगह इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जा रहा है। मंदिर परिसर में स्थापित करीब 40 दान पेटियां एक बार में खाली करने के बजाय अलग अलग दिनों में खाली की जा रही हैं। दास ने कहा, दान पेटी खाली करने से पूर्व गणना कक्ष से खाली पेटी लाने, उसे रखने और सीलबंद पेटी को गणना कक्ष में ले जाने की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। इसके लिए दो पेशेवर वीडियोग्राफर तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा, वहीं निगरानी टीम में दो बैंक कर्मचारी, न्यास के दो प्रतिनिधि, दो निजी सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। दान से भरी पेटी जब गणना कक्ष में पहुंचाई जाती है तो भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी उस पर सील लगाते हैं जिससे यह प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बन जाती है। उन्होंने कहा, ''दान की गणना वाले कक्ष में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब राम मंदिर में एक पैसा भी इधर से उधर नहीं जा सकता...सबकुछ सुरक्षित है। न्यास आगे भी इस व्यवस्था में सुधार करना जारी रखेगा।'' उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन सख्त हो जाए तो चोरी अपने आप रुक जाएगी।

न्यास में हाल ही में हुए बदलाव पर दास ने कहा कि न्यास की बैठक में लिए गए सभी निर्णय सभी को स्वीकार होंगे। उन्होंने कहा कि सावन मास में झूला उत्सव सहित धार्मिक परंपराएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी। राम मंदिर में चढावे की कथित चोरी की घटना के बाद विशेष जांच टीम का गठन किया गया।

न्यायालय ने मुसलमानों में बहुविवाह की प्रथा संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें मुसलमानों में बहुविवाह की प्रथा को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं वी. मोहना की पीठ ने महिला अधिकार कार्यकर्ता जकिया सोमन, नूरजहां सफिया नियाज और अन्य की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न कर दिया। याचिका में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82 को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ' के तहत मिलने वाली किसी भी छूट को हटाते हुए बहुविवाह के लिए समान रूप से सजा का प्रावधान करती है। इसमें केंद्र सरकार से बहुविवाह की प्रथा को खत्म करने के लिए कानूनी कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि चाहे कोई भी धर्म हो उसमें सभी नागरिकों के लिए इसे शुरूआत से ही 'अमान्य' माना जाए। मुस्लिम महिलाओं के कानूनी अधिकारों और संरक्षण के लिए कई अन्य निर्देश का अनुरोध करने के अलावा, याचिका में प्राधिकारों के पास सभी मुस्लिम शादियों और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण कराने के निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया गया, ताकि चोरी-छिपे होने वाली शादियों पर रोक लगाई जा सके।

तृणमूल सरकार के दौरान बीरभूम में 15,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ : शुभेंदु अधिकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बीरभूम जिले में पिछले 15 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है और पिछली सरकार के समर्थन के बिना ऐसा होना मुमकिन नहीं था। अधिकारी ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि पत्थरों के व्यापारी मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुल्लू मंडल के इर्द-गिर्द चल रहा यह गिरोह राजनीतिक संरक्षण और संस्थागत समर्थन के बिना इतने वर्षों तक नहीं चल सकता था। टुल्लू मंडल अभी फरार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सरकारी विभाग या तो मिलीभगत में शामिल थे या फिर ऊपर से मिले निर्देशों के तहत चुप रहे।

अधिकारी ने इस बात की ओर इशारा किया कि पुलिस की अब तक की जांच के अनुसार, मंडल ने पिछले कुछ वर्षों में 242 गाड़ियां, 21 संपत्तियां और 300 बीघा ज़मीन जमा कर ली थी। उन्होंने आरोप लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन के बिना, इतने बड़े गिरोह का इतने लंबे समय तक चलना नामुमकिन है।

उन्होंने कहा, एक इलाके में सिर्फ एक चीज (पत्थर के व्यापार) से 1,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी का मतलब है कि पिछले 15 साल से राज्य चलाने वाली सरकार सिर्फ एक जिले से सालाना 15,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान के लिए जिम्मेदार है। हम इस हेराफेरी से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले का पता लगाएंगे और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए बंगाल पुलिस पर पूरा भरोसा है।

अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के लिए काम कर रहा था ताहिर हुसैन : सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली/भाषा। आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि ''खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाला पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन परोक्ष रूप से भाजपा के लिए काम कर रहा था।'' फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर भाजपा द्वारा आप को जिम्मेदार ठहराए जाने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए भारद्वाज ने कहा कि दंगों से पहले हुसैन के भाजपा से राजनीतिक संबंध थे। उन्होंने कहा कि अंकित शर्मा हत्याकांड में हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होते ही आम आदमी पार्टी ने उसे तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जहां आप ने हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं भाजपा ने दंगों से जुड़े अन्य मामलों में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे नेताओं का समर्थन जारी रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि अब भाजपा इस मामले की जिम्मेदारी आप पर डालने की कोशिश कर रही है। इससे पहले, हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने हुसैन को ''संरक्षण'' दिया था। मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली की एक अदालत द्वारा हुसैन को दोषी ठहराया जाना इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दंगों को भड़काया था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने 25 सीटों पर तय किए उम्मीदवार : मायावती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने लगभग 25 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती ने वर्ष 2007 में अपने दम पर बसपा की बहुमत की सरकार बनाई। 2012 से पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरा है और 2022 के चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई थी। उप्र विधानसभा की 403 सीटें हैं। अपने आधिकारिक एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा कि चुनाव की तैयारी के लिए लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय कई बैठकें की जा चुकी हैं और आगे भी होंगी। इन बैठकों में प्रदेश और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों को उम्मीदवार चयन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने पोस्ट में कहा, साक्षात्कार लेकर अब तक लगभग दो दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। आगे भी सभी सीटों पर उम्मीदवारों का अंतिम फैसला मेरे द्वारा ही किया जाएगा। मायावती ने कहा कि उम्मीदवार चयन को लेकर राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद (बसपा प्रमुख के भतीजे) के संबंध में तरह-तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। पिछले दिनों मीडिया में यह खबरें आई थीं कि बसपा प्रमुख के भतीजे आकाश आनंद को उम्मीदवारों के चयन की ज़िम्मेदारी दी गई है। बसपा प्रमुख ने स्पष्ट किया कि न सिर्फ उप्र में, बल्कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप मैं ही देती हूं।

मायावती ने पोस्ट में कहा कि जिन सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं, वहां उनकी अनुमति से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी छोटी-बड़ी जनसभाएं कर घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में आकाश आनंद भी कुछ सीटों पर जनसभा कर उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे।

'कामकोटि के बारे में प्रियंका की टिप्पणी वैज्ञानिक, अकादमिक समुदाय का अपमान'

कानपुर (उप्र)/भाषा। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा की आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि के बारे में टिप्पणी को देश के वैज्ञानिक और अकादमिक समुदाय का अपमान करार दिया है।

प्रोफेसर पाठक ने पीटीआई-भाषा' के साथ बातचीत में कहा कि वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को राजनीतिक बहसों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे किसी राजनीतिक विचारधारा के बजाय समाज और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा, मैं भी शोधार्थी रहा हूं। जन-प्रतिनिधियों को वैज्ञानिकों के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। प्रियंका गांधी की कामकोटि के बारे में ''गोमूत्र विशेषज्ञ'' टिप्पणी पर पाठक ने कहा कि इस बयान से देश भर के वैज्ञानिकों और शिक्षकों की भावनाएं आहत हुई हैं। पाठक ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा में विद्वानों को हमेशा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और वैज्ञानिकों को उनके अकादमिक योगदान के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि राजनीतिक नजरिए से।

तसलीमा नसरीन 19 साल बाद कोलकाता लौटीं, उन्होंने इसे घरवापसी बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। निर्वासन में रह रहीं बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन शुक्रवार को लगभग 19 साल बाद कोलकाता लौटीं तथा उन्होंने इस यात्रा को उस शहर (कोलकाता) में भावनात्मक घरवापसी बताया जिसे वह आज भी अपना मानती हैं। उनका आगमन शनिवार को होने वाले एक साहित्यिक कार्यक्रम से ठीक पहले हुआ है जिसे पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के तहत राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

यहां हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए इंतजार कर रहे लोगों का नसरीन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह उनकी नवंबर 2007 के बाद कोलकाता की पहली यात्रा है। उस समय अपनी रचनाओं के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के कारण उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश से निर्वासन के बाद वह कोलकाता को अक्सर अपने घर जैसा सबसे निकट का स्थान बताया करती थीं। लेखिका यहां रवींद्र सदन में कट्टरपंथ-विरोधी साहित्यिक कार्यक्रम में पहली बार सार्वजनिक रूप से शामिल होंगी। उम्मीद है कि वह कार्यक्रम में कविता-पाठ करेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और मशहूर लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय एवं अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी एक साहित्यिक कार्यक्रम के तौर पर परिकल्पना की गयी, लेकिन प.बंगाल में भाजपा सरकार बनने के कुछ माह बाद तथा अभिव्यक्ति की आजादी, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक भावनाओं के प्रति राज्य के रवैये पर फिर से शुरू हुई बहस के बीच यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से अहम हो गया है।

यात्रा से पहले, नसरीन ने कहा था कि कोलकाता लौटना ''उन्हें अपने ही देश'' में लौटने जैसा लगता है। उन्होंने कहा था, ''मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही देश लौट रही हूं। मेरे दिल में बंगाल कभी भी किसी सीमा या कंटीले तारों की बाड़ से बंटा नहीं रहा। बंगाल के पूर्वी हिस्से का दरवाजा मेरे लिए बंद है, इसलिए अभी के लिए, बंगाल का यही हिस्सा मेरा घर है।'' वह खुशी, लेकिन साथ ही 'दर्द' के साथ लौट रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें याद आया कि कोलकाता ने उन्हें घर, दोस्त, पाठक और अपनापन दिया था, लेकिन बाद में उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया गया।

इस यात्रा को सिर्फ निजी तौर पर घर वापसी से कहीं अधिक बताते हुए नसरीन ने कहा कि यह उस आवाज की वापसी का प्रतीक है जिसे धार्मिक कट्टरपंथियों ने कभी दबाने की कोशिश की थी। अपने उपन्यास 'लज्जा' को लेकर मिली जान से मारे जाने की धमकियों के कारण 1994 में बांग्लादेश से भागने के बाद, नसरीन 2004 में कोलकाता में बस गईं और बांग्ला भाषी इस शहर को निर्वासन के दौरान अपनी सांस्कृतिक शरणस्थली के रूप में अपनाया।

पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा का 96 साल की उम्र में निधन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व सेना प्रमुख (सेवानिवृत्त) जनरल विश्वनाथ शर्मा का शुक्रवार को 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारतीय सेना ने यह जानकारी दी। जनरल शर्मा 30 जून 1988 से 30 जून 1990 तक सेना प्रमुख के पद पर रहे थे। उन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाहौर सेक्टर में मेजर के रूप में युद्ध में हिस्सा लिया था।

पूर्व सेना प्रमुख ने बख्तरबंद रेजिमेंट की कमान संभाली और सेना में कई महत्वपूर्ण स्टाफ तथा प्रशिक्षण संबंधी जिम्मेदारियां निभाईं। जनरल शर्मा को 1965 के युद्ध के बाद ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत किया गया। सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जनरल शर्मा ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में एक माउंटेन ब्रिगेड की कमान संभाली और उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए 1977 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने बाद में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बख्तरबंद ब्रिगेड की कमान संभाली।

वर्ष 1980 में जनरल शर्मा को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में एक माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली। वर्ष 1984 में वह लेफ्टिनेंट जनरल बने और पश्चिमी क्षेत्र में एक कोर की कमान संभाली। उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अनुभवी सैन्य अधिकारी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सेना ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ और भारतीय सेना के सभी रैंक के जवान परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, एडीसी और पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। भारतीय सेना उनके शोक संतप्त परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व सेना प्रमुख के निधन पर शोक जताया और कहा, एक उत्कृष्ट सैनिक के रूप में जनरल शर्मा ने अटूट समर्पण, साहस और सम्मान के साथ देश की सेवा की। उनका जन्म चार जून 1930 को हुआ था।

विहिप और संत समाज ने संसद परिसर में भगवा वेश में विपक्ष के प्रदर्शन की निंदा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को उजागर करने के लिए संसद परिसर में भगवा कपड़े पहनकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और विपक्ष के अन्य सांसदों द्वारा किए गए 'एक नाटक' की शुक्रवार को निंदा की एवं कहा कि इस प्रदर्शन से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान हुआ है। राममंदिर और अयोध्या की धार्मिक संस्थाओं से संबद्ध कई प्रमुख संतों एवं पदाधिकारियों ने भी इस विरोध-प्रदर्शन की आलोचना की तथा इसमें शामिल सांसदों के निष्कासन की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से प्रदर्शन में शामिल सांसदों की सदस्यता रद्द करने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी चढ़ावा चोरी के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल थे।

संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसदों ने 'चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए। सांसदों ने मकर द्वार की सीढ़ियों के सामने दान-पात्र रखे और निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उन बक्सों के पास बैठ गए। राजेश रंजन पप्पू यादव के नाम से भी जाने जाते हैं। एक नाटक के तौर पर, राहुल गांधी समेत सांसदों ने बक्सों में पैसे डाले, जबकि गेरुआ कपड़े पहने यादव ने राम मंदिर में कथित चोरी को दिखाने के लिए पैसे अपनी जेब में डाल लिए। एक वीडियो बयान में, विहिप के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित यादव तथा गांधी और कांग्रेस के अन्य सांसदों एवं समाजवादी पार्टी के अन्य सांसदों ने हिंदू संतों के कपड़े पहनकर अभद्र' विरोध प्रदर्शन किया। जैन ने कहा, विहिप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है। हम लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वह उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि कोई भी इस तरह हिंदू आस्था का अपमान करने की हिम्मत न करे।

उन्होंने आरोप लगाया, संत का वेश धारण करके उन्होंने न केवल संतों का अपमान किया है, बल्कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। रामायण से तुलना करते हुए जैन ने कहा, जिस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए संत का वेश धारण किया था, क्या अब वे संत का वेश धारण करके हिंदू धर्म पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कभी संभव नहीं होगा। उन्होंने विपक्षी नेताओं को मौलवी या पादरी का भेष धारण कर इन धर्मों का मजाक उड़ाने की चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वे केवल हिंदू मान्यताओं को निशाना बना सकते हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने एक वीडियो बयान में कहा,कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, अन्य कांग्रेस सांसदों और पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर सनातन धर्म का अपमान करने के लिए संसद परिसर का गलत इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है।

सुविचार

कर्म ही पूजा है। अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें, परिणाम की चिंता कम करें। सच्ची लगन रखें, सफलता निश्चित है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

'वंदे मातरम्' का विरोध क्यों?

संसद ने 'राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' को पारित कर उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है, जो 'वंदे मातरम्' का उद्घोष कर भारत मां के लिए बलिदान हुए थे। इस गीत में अद्भुत ऊर्जा है। जो व्यक्ति इसे गाता है, उसके तन और मन में देशभक्ति की लहर पैदा हो जाती है। अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने में जब अत्याचारी पुलिस अधिकारी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों पर लाठियां और कोड़े बरसाते थे, तब उन्हें हर वार के जवाब में 'वंदे मातरम्' सुनने को मिलता था। अत्याचारी मार-मार कर थक जाते थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों का जोश कम होने का नाम नहीं लेता था। दुर्भाग्य की बात है कि आज जब 'वंदे मातरम्' को कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है तो विपक्ष के कुछ राजनेताओं को यह कदम संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ लग रहा है! 'वंदे मातरम्' सुनकर अंग्रेज चिढ़ते थे। उनके रहमो-करम पर पलने वाले सरकारी अधिकारी भड़कते थे। अब तो भारत आज़ाद है। अगर यहां 'वंदे मातरम्' नहीं गाया जाएगा तो कहां गाया जाएगा? जो नेतागण इसका विरोध कर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, वे एक बार इसका सही अनुवाद पढ़ें। इसमें भारत भूमि की सुंदरता और विविधता का वर्णन है। इसके शब्दों में देश की दिव्य शक्तियों का बखान है। भले ही कोई व्यक्ति इसका अर्थ न जानता हो, अगर वह शुद्ध भाव के साथ इसे गाता है तो दिव्यता को महसूस करता है। इस पर आपत्ति जताने के लिए कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए। जिस गीत ने स्वतंत्रता की चेतना जगाई, देशवासियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए शक्ति दी, उसका सम्मान करना गर्व का विषय होना चाहिए। 'वंदे मातरम्' का सम्मान उन बलिदानियों का भी सम्मान है।

कुछ लोगों ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर रखा है। वे अजीब तर्क दे रहे हैं। जैसे- ''वंदे मातरम्' गाने से क्या हो जाएगा? क्या इससे रोटी मिल जाएगी?' इनसे कोई पूछे- 'क्या 'वंदे मातरम्' न गाने से सबकुछ हो जाएगा? क्या इसे नहीं गाएंगे तो छप्पन तरह के पकवान मिल जाएंगे?' मनुष्य को पेट भरने के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। हर काम दाल-रोटी के लिए नहीं होता है। राष्ट्र का गौरव भी होता है, जिसे याद करना चाहिए। बलिदान का इतिहास भी होता है, जिसे भूलना नहीं चाहिए। जो लोग आज 'वंदे मातरम्' न गाने के लिए तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए- अगर डेढ़ सौ साल पहले सभी लोगों की यह सोच होती कि आज़ादी की लड़ाई से क्या हो जाएगा, क्या इससे रोटी मिल जाएगी, क्या इससे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्या इससे मुफ्त इलाज मिल जाएगा, क्या इससे दैनिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी, क्या इससे चीजें सस्ती हो जाएंगी ... तो इस देश का क्या होता? हमारा क्या होता? अंग्रेजी राज में 'वंदे मातरम्' गाने का मतलब था- जेल, पिटाई और फांसी! फिर भी हमारे पूर्वजों ने ज़िद नहीं छोड़ी थी। वे जेल गए, पिटाई बर्दाश्त की, फंदों पर लटके, लेकिन यह उद्घोष कभी शांत नहीं हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था कि वे आज़ाद हिन्दुस्तान में 'वंदे मातरम्' गाएं। कई तो मन में यह आस लेकर ही बलिदान हो गए थे। आज उसी देश में कुछ लोग 'वंदे मातरम्' के खिलाफ बातें कर रहे हैं! अगर हम अपने राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी पर उसका कैसा असर होगा? क्या वह देश का इतिहास नहीं भूल जाएगी? क्या वह त्यागी और बलिदानी योद्धाओं का सम्मान करना सीखेगी? उसे तो यही लगेगा कि अंग्रेज भ्रमण करते-करते भारत आए और एक दिन चाय-नाश्ता कर ब्रिटेन लौट गए थे। क्या हम यह सीख देना चाहेंगे? देश को बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद आज़ादी मिली थी। हमें इसके प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए।

ट्वीटर टॉक

22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीतने के लिए भारतीय पुरुष और महिला टीमों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं!इन दोनों टीमों ने अपने शानदार प्रदर्शन, अनुशासन और ज़बरदस्त टीम भावना से पूरे देश को गर्व से भर दिया है।

-भजनलाल शर्मा

मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह के शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो वीरता, बहादुरी और बहादुरी दिखाई, वह सदियों तक भारत माता की सेवा में मिसाल बनी रहेगी।

-योगी आदित्यनाथ

राज्य में विकास के कामों का जारी रहना और उन्हें समय पर पूरा करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ, पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित सड़क प्रोजेक्टस को बड़ी राहत देते हुए, बिना लिक्विडेटेड डैमेज के प्रोजेक्ट का समय 4 महीने करने का एक अहम फैसला लिया गया है।

-दिया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

अनुराग का विरल उदाहरण

दिल्ली प्रदेश 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' अतीत में विशेष अवसरों पर साहित्य से जुड़े समारोह आयोजित करवाता था। एक बार 31 जुलाई को प्रेमचंद-जयंती आने वाली थी। गोपाल कृष्ण कौल दिल्ली प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साहित्य मंत्री थे और उसकी रंगमंच परिषद के भी मंत्री थे। गोपालप्रसाद व्यास सम्मेलन के प्रधानमंत्री थे। तय किया गया कि प्रेमचंद जयंती पर प्रेमचंद की कहानी 'पंचपरमेश्वर' का नाट्य रूपांतर करके मंच पर प्रस्तुत किया जाए। नाट्य रूपांतर कौल साहब ने किया और उसके प्रस्तुतीकरण का जिम्मा भी उन्हीं पर था। उस नाट्य रूपांतर पर भूमिका लिखने और सप्रू हाउस में उसकी प्रस्तुति का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से प्रार्थना की गई। उन्होंने इसकी सहर्ष स्वीकृति देने की कृपा की, भूमिका लिखी और प्रेमचंद-जयंती के दिन सप्रू हाउस के मंच पर उसका यथोचित उद्घाटन भी किया। उन्होंने उस नाट्य रूपांतर को मुक्त कंठ से सराहा और 'पंचपरमेश्वर' में वर्णित हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे और ग्रामीण पंचायती न्याय के महत्त्व पर विशद एवं विशेष प्रकाश डाला।

सामयिक

आंदोलन की संस्कृति : अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी आवश्यक

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

भविष्य के लिए कुछ स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रत्येक बड़े आंदोलन के लिए पूर्व अनुमति, निर्धारित मार्ग, आयोजकों की स्पष्ट जवाबदेही, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा की स्थिति में त्वरित पहचान और दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही पुलिस को भी भीड़ नियंत्रण के आधुनिक, वैज्ञानिक और न्यूनतम आवश्यक बल के सिद्धांतों पर निरंतर प्रशिक्षित किया जाए। इससे नागरिक अधिकारों और कानून-व्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन स्थापित होगा।

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संवाद, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं का जीवंत तंत्र है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार प्राप्त है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार कभी भी हिंसा, अराजकता, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश या सुरक्षा बलों पर हमले का लाइसेंस नहीं बन सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह विरोध को भी सम्मान देता है, किंतु विरोध की भी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। हाल के वर्षों में कुछ आंदोलनों ने यह गंभीर प्रश्न खड़ा किया है कि क्या लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में कानून और व्यवस्था को चुनौती देना स्वीकार्य हो सकता है? यदि कोई प्रदर्शन बैरिकेड तोड़ने, पुलिस पर हमला करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थान की ओर जबरन बढ़ने का प्रयास करे, तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे केवल मूकदर्शक बनी रहें। राज्य का पहला दायित्व नागरिकों की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैलेट गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए यह कहना कि असाधारण परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसी संतुलित दृष्टिकोण का परिचायक है। न्यायालय ने किसी भी प्रकार के असीमित बल प्रयोग को उचित नहीं ठहराया, बल्कि यह स्पष्ट संकेत दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के पास आवश्यक साधन भी होने चाहिए। यदि सुरक्षा बलों से हर प्रभावी उपाय छीन लिया जाएगा, तो हिंसक भीड़ पर नियंत्रण कैसे स्थापित होगा? यह प्रश्न केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार मिल जाने चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा और जवाबदेही के दायरे में रहती है। यदि कहीं बल प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ हो, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जांच का आधार तथ्य होने चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं। जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों की पीड़ा सुनी जानी चाहिए, उसी प्रकार घायल हुए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों का पक्ष भी उतनी ही गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन की संस्कृति पर पुनर्विचार किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की ऐसी परंपरा विकसित की थी, जिसमें नैतिक बल सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह में विरोध था, परंतु वैमनस्य नहीं। संघर्ष था, परंतु हिंसा नहीं। दृढ़ता थी, परंतु अराजकता नहीं। दुर्भाग्य से आज कुछ आंदोलनों में संवाद की जगह टकराव, संयम की जगह उग्रता और तर्क की जगह भीड़ की शक्ति को महत्व दिया जाने लगा है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में परिवर्तन सड़क पर पत्थर फेंकने से नहीं, बल्कि विचार, संगठन, जनजागरण और संवैधानिक प्रक्रियाओं से आता है। यदि हर असहमति हिंसक रूप ले लेगी, तो सबसे अधिक नुकसान उन्हीं युवाओं का होगा, जिनके भविष्य के नाम पर आंदोलन किए जाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन और उत्तरदायित्व से होती है।

यदि यह मान लिया जाए कि किसी राजनीतिक दल या उसके समर्थकों द्वारा आयोजित आंदोलन में कुछ असामाजिक और हिंसक तत्वों ने प्रवेश कर उसे अराजक दिशा देने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में सरकार का प्राथमिक दायित्व कानून-व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। समय रहते प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई, भले ही उससे कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हों, व्यापक अराजकता और राष्ट्रीय संस्थानों को संभावित क्षति से बचाने के उद्देश्य से देखी जा सकती है। साथ ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह भी अपेक्षित है कि विपक्ष जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंसा और तोड़फोड़ से स्पष्ट दूरी बनाए तथा वैध मांगों के समर्थन और अवैध कृत्यों के विरोध के बीच स्पष्ट रेखा खींचे। लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होता है जब सरकार कानून के शासन का पालन करे, विपक्ष जिम्मेदार आचरण करे और आंदोलन संविधान की मर्यादाओं एवं शांतिपूर्ण तरीकों के भीतर संचालित हों।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी दल का यह दायित्व है कि वह जनभावनाओं को सकारात्मक दिशा दे। यदि कोई राजनीतिक संगठन या उसके समर्थक आंदोलन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ या कानून हाथ में लेने को प्रोत्साहित करते हैं, तो उसकी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। विपक्ष लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है, लेकिन उसका धर्म केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना भी है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा जनआंदोलनों का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, तो अंततः लोकतंत्र ही कमजोर होता है। सरकारों को भी यह आत्ममंथन करना चाहिए कि जनआक्रोश की स्थितियां क्यों बनती हैं। संवाद के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। पारदर्शी निर्णय, समय पर संवाद और शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था अनेक आंदोलनों को उग्र होने से पहले ही शांत कर सकती है। लोकतंत्र में शासन का अर्थ केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि विश्वास अर्जित करना भी है।

भविष्य के लिए कुछ स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रत्येक बड़े आंदोलन के लिए पूर्व अनुमति, निर्धारित मार्ग, आयोजकों की स्पष्ट जवाबदेही, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा की स्थिति में त्वरित पहचान और दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही पुलिस को भी भीड़ नियंत्रण के आधुनिक, वैज्ञानिक और न्यूनतम आवश्यक बल के सिद्धांतों पर निरंतर प्रशिक्षित किया जाए। इससे नागरिक अधिकारों और कानून-व्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन स्थापित होगा। लोकतंत्र का सौंदर्य इस बात में नहीं कि कितनी जोर से नारे लगाए गए, बल्कि इस बात में है कि कितनी गंभीरता से संवाद हुआ। संसद जनता की आकांक्षाओं का मंदिर है। यदि कोई समूह अपनी बात संसद तक पहुंचाना चाहता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन संसद पर दबाव बनाने या उसे घेरने की संस्कृति लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करती है। लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है, भीड़तंत्र नहीं।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ-साथ विश्वगुरु बनने की दिशा में भी अग्रसर है। ऐसे समय में हमें विरोध की भी ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी जो विश्व के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करे। हमारे आंदोलन व्यवस्था को तोड़ने के नहीं, व्यवस्था को बेहतर बनाने के माध्यम बनें। हमारे प्रदर्शन राष्ट्र को विभाजित करने के नहीं, लोकतांत्रिक चेतना को समृद्ध करने के साधन बनें। अंततः यह स्मरण रखना होगा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब कर्तव्यों का भी समान रूप से पालन किया जाए। यदि आंदोलन संविधान की मर्यादाओं में रहकर होंगे, तो सरकार भी अधिक उत्तरदायी बनेगी और लोकतंत्र भी अधिक सशक्त होगा। भारत को ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता है जो व्यवस्था को चुनौती देने के बजाय उसे सुधारने की प्रेरणा दें। जो युवाओं को उग्रता नहीं, उत्तरदायित्व सिखाएं और जो राष्ट्रहित को दलगत हितों से ऊपर रखकर लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व, अनुशासित तथा जनोन्मुख बनाने का मार्ग प्रशस्त करें।

नजरिया

सामाजिक सद्भाव की परीक्षा और नेपाल सरकार की विफलता

अशोक भाटिया

मोबाइल : 9221232130

नेपाल, जिसे दुनिया बुद्ध की शांति-भूमि और बहुसांस्कृतिक सह-अस्तित्व के एक अनुपम उदाहरण के रूप में जानती है, आज एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। भारत के बिहार राज्य की सीमा से सटे सुनसरी जिले के कप्तानगंज से शुरू हुई चिंगारी ने देखते ही देखते मधेश और कोशी प्रांत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। सावन के पवित्र महीने में पारंपरिक बोलबम/कांवड़ यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने और धार्मिक झंडों के प्रदर्शन को लेकर उपजा एक मामूली सा विवाद आज एक भयावह सांप्रदायिक हिंसा का रूप अख्तियार कर चुका है। इस हिंसा में अब तक तीन बेगुनाह नागरिकों-ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता और गणेश यादव-की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं। कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाओं पर आंशिक पाबंदी और सड़कों पर गश्त करती सेना इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि नेपाल का सामाजिक ताना-बाना इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है।

यह विवाद 26 जुलाई 2026 की रात सुनसरी जिले की देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज इलाके में तब शुरू हुआ, जब दो अलग-अलग समुदाय अपने धार्मिक आयोजन कर रहे थे। एक पक्ष की धार्मिक यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज और प्रतीकों के प्रदर्शन को लेकर दोनों गुटों में तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। स्थानीय प्रशासन और खुफिया तंत्र की घोर लापरवाही के कारण इस शुरुआती विवाद को समय रहते शांत नहीं किया जा सका। स्थिति तब और अनियंत्रित हो गई जब उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग और गोलीबारी का सहारा लेना पड़ा, जिसमें एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। इस मौत की खबर आग की तरह फैली और इसने सुलगते असंतोष को पूरे क्षेत्र में भड़का दिया। इसके बाद हिंसा का यह दौर सुनसरी से निकलकर सिराहा, धनुषा, पर्सा और जनकपुरधाम जैसे प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंच गया। कई स्थानों पर आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है।

दरअसल यह हिंसा केवल दो समुदायों की आपसी कट्टरता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह नेपाल के प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र की एक बहुत बड़ी विफलता है। सुरक्षा मामलों के जानकारों और पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि सुनसरी की घटना से काफी पहले ही तराई के इलाकों में सांप्रदायिक तनाव के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय प्रशासन, नेपाल पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब कोई संवेदनशील धार्मिक त्योहार या यात्रा आयोजित होती है, तो प्रशासन का यह प्राथमिक कर्तव्य होता है कि वह पहले से ही दोनों पक्षों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठकें करे, रूट तय करे और लाउडस्पीकर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कड़े नियम लागू करे। कप्तानगंज में ऐसा कोई पूर्व-नियोजित प्रयास दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा, जब हिंसा भड़की, तो केंद्र सरकार की ओर से त्वरित राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बेहद देरी से हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' सहित कई सांसदों ने संसद में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठाया है कि जब मधेश जल रहा था, तब देश के शीर्ष नेतृत्व ने सर्वदलीय बैठक और शांति बहाली के प्रयासों में इतनी देरी क्यों की।

तराई-मधेश क्षेत्र में भड़की इस हिंसा का प्रभाव केवल नेपाल की आंतरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने भारत-नेपाल की खुली सीमा की संवेदनशीलता और दोनों देशों के बीच चलने वाले द्विपक्षीय व्यापारिक गलियारे के सामने भी गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। सुनसरी, पर्सा और सिराहा जैसे अशांत जिले भारत के बिहार राज्य के सीमावर्ती इलाकों से सीधे जुड़े हुए हैं। इस भू-राजनीतिक जुड़ाव के कारण नेपाल में उपजा कोई भी सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव बहुत तेजी से सीमा पार भारतीय क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अचानक बढ़े इस तनाव को देखते हुए भारत के सशस्त्र सीमा बल और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रहना पड़ रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच नागरिकों की सामान्य आवाजाही और आपसी सामाजिक रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं।

इससे भी बड़ा संकट आर्थिक मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। रक्सौल-वीरगंज, जोगबनी-विराटनगर और जयनगर-जनकपुर जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग नेपाल की जीवनरेखा माने जाते हैं। नेपाल अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं, ईंधन, दवाओं और औद्योगिक कच्चे माल के लिए 70 प्रतिशत से अधिक भारत से होने वाले आयात पर निर्भर है। मधेश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, सड़कों पर तोड़फोड़ और असुरक्षा के माहौल के कारण मालवाहक ट्रकों के पहिए थम गए हैं। सीमा पार माल की आवाजाही रुकने से नेपाल के बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत होने लगी है, जिससे महंगाई बेलगाम होने का खतरा पैदा हो गया है। लंबे समय तक चलने वाली ऐसी अशांति दोनों देशों के बीच प्रस्तावित और निर्माणाधीन रणनीतिक आर्थिक गलियारों, रेलवे कनेक्टिविटी परियोजनाओं और व्यापारिक बुनियादी ढांचों के विकास की गति को धीमा कर देती है। कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना या विदेशी निवेशक ऐसे अशांत क्षेत्रों में पूंजी लगाने से कतराता है। यदि नेपाल सरकार ने इस हिंसा पर तुरंत काबू पाकर सीमावर्ती व्यापारिक मार्गों को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू नहीं किया, तो पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रही नेपाल की अर्थव्यवस्था को ऐसा गहरा आर्थिक झटका लग सकता है, जिससे उबरने में देश को लंबा समय लगेगा।

साल 2008 में राजशाही की समाप्ति के बाद नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। सदियों से नेपाल में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और किरात समुदाय के लोग आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक तालमेल के साथ रहते आए हैं। विशेषकर भारत से सटे तराई-मधेश क्षेत्र की एक अनूठी पहचान रही है, जहां सीमा के दोनों ओर के सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध समाज को एक सूत्र में बांधकर रखते हैं। परंतु, पिछले कुछ समय से इस शांत सामाजिक धरातल के नीचे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक खतरनाक राजनीति पनपती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नफरत फैलाने वाले भाषणों, अफवाहों और भड़काऊ वीडियोज ने इस आग में घी डालने का काम किया है। उपद्रवी तत्वों द्वारा इस संवेदनशील स्थिति का फायदा उठाकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना और समाज में डर का माहौल पैदा करना यह दर्शाता है कि इस हिंसा के पीछे कुछ निहित स्वार्थी तत्व सक्रिय हैं, जो नेपाल की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करना चाहते हैं।

नेपाल इस समय एक चौराहे पर खड़ा है। कर्फ्यू और संगीनों के साये में कायम की गई शांति कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। यदि तराई-मधेश में स्थायी शांति बहाल करनी है, तो बहुस्तरीय प्रयास करने होंगे:राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सद्भाव, सुलह और भाईचारे की भावना ही नेपाली समाज की अद्वितीय पहचान है। नेपाल जैसे बहुसांस्कृतिक और विकासशील देश के लिए आंतरिक स्थिरता ही आर्थिक और सामाजिक प्रगति की पहली शर्त है। सुनसरी की घटना एक कड़वी चेतावनी है कि यदि हमने अपनी साझी विरासत और आपसी विश्वास को सहेजकर नहीं रखा, तो नफरत की यह आग किसी का भी भला नहीं करेगी। अब समय आ गया है कि नेपाल का नागरिक समाज, सरकार और आम जनता एकजुट होकर इन विघटनकारी ताकतों को नाकाम करें। बंदूक की गोलियों और कर्फ्यू के साये से बाहर निकलकर, संवाद और सहिष्णुता के रास्ते पर चलकर ही नेपाल फिर से शांति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कप्तानगंज जैसी पुनरावृत्ति देश के किसी भी कोने में न हो।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद महिलाओं की जिंदगी बयां करती है 'सिटी आफ विडोज़'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिकी सेनाएं फरवरी 2020 में अफगानिस्तान को उसके नए शासक तालिबान के हवाले करके लौट रही थीं लेकिन तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद देश की उन आजाद ख्याल महिलाओं पर क्या बीती जो पिछले 20 सालों में देश में नेतृत्वकारी भूमिकाएं संभाल रही थीं। प्रसिद्ध लेखिका नादिया हाशमी का नवीनतम उपन्यास 'सिटी आफ विडोज़' ऐसी ही अफगानी महिलाओं की जिंदगी पर केंद्रित है जिनकी दुनिया तालिबान के पुन: सत्ता पर कब्जा करने के बाद रातोंरात बदल गई थी। प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स द्वारा यहां जारी एक बयान के अनुसार, यह उपन्यास एक दिलचस्प और डरावनी लेकिन आखिर में उम्मीद जगाने वाली कहानी बयां करता है। यह कहानी तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद के सालों में अफ़गानिस्तान की महिलाओं की ज़िंदगी पर आधारित है। फरवरी 2020 में, लगभग बीस साल के कब्ज़े के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलानी शुरू कर दी थीं। इन बीस सालों में अफ़गानी महिलाओं की एक ऐसी पूरी पीढ़ी बड़ी हुई थी जो आजाद ख्याल थी और जिंदगी के हर मोर्चे पर अगुवाई कर रही थी। किताब की प्रस्तावना में कहा गया है कि ये महिलाएं जो काफी हद तक शांति के माहौल में पली-बढ़ीं थीं, स्कूल गई थीं, नौकरी-पेशा थीं और यहां तक कि उन्होंने सेना और संसद में भी काम किया था। अफ़गानिस्तान की इन्हीं महिलाओं ने देखा कि तालिबान फिर से सड़कों पर कब्ज़ा कर रहा है। उन्हें पता था कि सब कुछ बदलने वाला है। किताब की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है कि काबुल जैसे हलचल भरे और आधुनिक शहर में महिलाएं टीवी न्यूज़कास्टर, दुकान की मालकिन, डॉक्टर, शिक्षक, वकील और यहां तक कि सैनिक भी हैं। इनमें मरजान भी शामिल है, जिसने अफ़गानी सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी और अब वह अपनी बेटी हवा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

किताब के अनुसार, पहले मरजान का नाम रहीमा था और वह 'बाचा पोश' की तरह रहती थी-यानी एक ऐसी लड़की जिसे बड़ी होने तक लड़के की तरह पाला-पोसा गया। रहीमा ने अपने पूर्व सैनिक पति के चंगुल से छूटने के बाद मरजान नाम अपना लिया। उसने अपने लिए एक नई ज़िंदगी बनाई थी जिसे वह आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी। तालिबान के राज में भी नहीं। इसी प्रकार, होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाकर सेना की सिर्फ़ महिलाओं वाली कॉम्बैट फ़ोर्स की अगुवाई करने वाली सोराया अब एक 'वॉन्टेड' महिला है। उसका भाई उसे तालिबान से बचाने के लिए पनाह देने को राजी नहीं है। उसका क्या होगा? या मीना, एक पत्रकार और ब्रॉडकास्टर, जिसका खूबसूरत चेहरा काबुल में हर कोई जानता है-यहां तक कि नई सरकार के लोग भी? अपनी काबिलियत के दम पर खड़ी हुईं इन अफगानी महिलाओं के सामने अब तालिबान के राज में क्या विकल्प है? लड़ें या भाग जाएं? या कोई तीसरा रास्ता ढूंढें? एक बात तो पक्की है: इनमें से कोई भी महिला चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार नहीं करेगी। हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित 'सिटी आफ विडोज़' इसी डर, विरोध, बदलाव और नई शुरुआत की एक कहानी है जो इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ी उन अविस्मरणीय अफ़गानी महिलाओं की आवाज़ बनती है। 'दी पर्ल दैट ब्रोक इट्स शैल' बेस्टसेलर समेत चार किताबों की लेखिका नादिया हाशमी अप्रवासी अफगानी माता पिता की संतान हैं। पेशे से बाल रोग चिकित्सक नादिया इस समय अमेरिका में रहती हैं।

विरोध

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शुक्रवार को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और रात्रि ड्यूटी समाप्त करने जैसी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करतीं आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील कार्यकर्ता।

स्पेन के सेउटा में 60000 लोग हुए दाखिल

सेउटा/एपी। पिछले 24 घंटों में मोरक्को से लगभग 60,000 प्रवासी स्पेन के सेउटा में दाखिल हुए हैं। सेउटा के प्रशासनिक प्रमुख ने यह जानकारी दी। यह संख्या सेउटा शहर की नियमित जनसंख्या के 70 फीसद के बराबर है। सेउटा के प्रशासनिक प्रमुख जुआन जीसस विवास के अनुसार प्रवासन की इस प्रक्रिया में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गयी। उन्होंने शुक्रवार को कहा, ''सेउटा जिस स्थिति से गुज़र रहा है, वह बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है।'' बृहस्पतिवार को सीमा पर भड़का संकट शुक्रवार को भी जारी रहा जहां सीमा के मोरक्को वाले क्षेत्र में सुरक्षाबलों एवं प्रवासियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने शुक्रवार को सेउटा में अपने संबोधन में सीमा उल्लंघन की निंदा की और इन घटनाओं को स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का 'उल्लंघन' बताया। स्पेन के नेता ने मानव तस्करों को दोषी ठहराते हुए कहा कि वे बहुत से युवाओं को बहकाते हैं और अंततः उनमें से कई को मौत के मुंह में धकेल देते हैं - ''चाहे वह समुद्र में हो या, जैसा कि इस मामले में हुआ, स्पेन की सीमा पर स्वायत्त शहर सेउटा में।'' सीमा के सीधे प्रसारण में नजर आ रहा है कि सेउटा के ऊपर एक पहाड़ी पर सैकड़ों प्रवासी जमा थे, जिन्हें मोरक्को की सेना ने आंसू गैस के गोले दागकर तितर-बितर कर दिया, जबकि अन्य लोग तैरकर स्पेनिश क्षेत्र की ओर बढ़ते रहे।

अस्मिता, हर्ष और यामिनी ने जूडो में फाइनल में पहुंच कर पदक पक्के किये

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ग्लास्गो/भाषा। भारतीय जूडो खिलाड़ियों ने शुक्रवार को यहां जारी राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कम से कम तीन रजत पदक सुनिश्चित कर दिए। अस्मिता डे, हर्ष सिंह और यामिनी मौर्य ने अपने-अपने वर्ग के फाइनल में जगह बनाकर ये पदक पक्के किये। महिला 48 किग्रा वर्ग में युवा खिलाड़ी अस्मिता डे ने बेहद रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड की समर शॉ को युको' के आधार पर हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एक समय हार की कगार पर पहुंच चुकीं अस्मिता ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। स्वर्ण पदक के मुकाबले में उनका सामना कनाडा की हेइडी क्राच से होगा।

इससे पहले अस्मिता ने स्कॉटलैंड की ईवा इविंग को 'इप्पोन' से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई थी। जूडो में 'इप्पोन' को सर्वोच्च स्कोर माना जाता है जिसके मिलते ही मुकाबला समाप्त हो जाता है। युको' अपेक्षाकृत कम अंक वाला स्कोर है।

पुरुष 60 किग्रा वर्ग में हर्ष सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के पेड्रो कार्लोस एंटुन नेटो को वाजा-आरी' के आधार पर हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले हर्ष ने क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के सफर में मलावी के चिकोंडी काथेवेरा को इप्पोन' से मात दी और फिर वानुआतु के एलन मोंथुएल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

फाइनल में हर्ष का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काटज से होगा। जूडो में वाजा-आरी' दूसरा सबसे बड़ा स्कोर होता है, जो खिलाड़ी को मुकाबले में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाता है। महिला वर्ग में यामिनी मौर्य ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका की डोने ब्रेटेनबाख को इप्पोन' से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में उनका सामना इंग्लैंड की असेल्या टोपराक से होगा।

इससे पहले यामिनी ने घाना की फ्रेमा अग्येई को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। महिला 52 किग्रा वर्ग में श्रद्धा कदुबाल चोपड़े पदक की दौड़ से बाहर हो गईं। रेपेचेज मुकाबले में उन्हें वेल्स की लोला हॉडसन ने युको से हराया।

श्रद्धा ने इससे पहले सिएरा लियोन की जेन मासाक्रॉई को इप्पोन से पराजित किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टिंका ईस्टन के खिलाफ उन्हें हार मिली। पुरुष 66 किग्रा वर्ग में रोहित बसीर मजगुल का सफर भी रेपेचेज में समाप्त हो गया। उन्हें इंग्लैंड के माइकल फ्रायर ने युको' के आधार पर हराया। इससे पहले रोहित ने मोजाम्बिक के सैमुअल रिबेरो को मात दी थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में साइप्रस के पेट्रोस क्रिस्टोडुलिडेस से हार गए थे।

संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी ने हाउस हेल्प को बचाने का किया दावा

मुंबई/एजेन्सी। मुंबई की टीवी अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने एक घरेलू सहायिका से जुड़ी घटना का खुलासा किया। उन्होंने दावा किया है कि उनकी घरेलू सहायिका गुड़िया की बड़ी बहन को नवी मुंबई के खारघर इलाके में एक घर में कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया था और उसे जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि महिला ने मदद के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उसे वहां से बाहर निकालने में मदद की। संभावना और अविनाश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ''इस मामले को सामने लाने का हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है। ऐसी घटनाएं किसी के भी आसपास हो सकती हैं, इसलिए लोगों को अपने आसपास होने वाली गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।''अविनाश ने वीडियो में बताया, ''घटना तब सामने आई, जब हमारी हाउस हेल्प गुड़िया अचानक रोने लगी। गुड़िया हमारे घर में रहती है और अचानक उसके रोने से हम चिंता में आ गए।

फिल्म डीसी का ट्रेलर रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

मुंबई सन पिक्चर्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म डीसी का एक्शन और रोमांच से भरपूर ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। ट्रेलर दर्शकों को अपराध, जुनून और ज़िंदगी की जंग से भरी एक खतरनाक दुनिया की झलक दिखाता है। मशहूर निर्देशक लोकेश कनगराज इस फिल्म से पहली बार बतौर अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आएंगे, वहीं उनके साथ वामिका गब्बी लीड रोल में हैं। यह तमिल रोमांटिक एक्शन थ्रिलर 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया के हिंदी भाषी बाज़ार (कब्ज़) में धर्मा प्रोडक्शंस रिलीज़ करेगा। जेलर, बीस्ट, अन्नात्थे और सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मशहूर सन पिक्चर्स एक बार फिर बड़े कैनवास की मनोरंजक फिल्म लेकर आया है। निर्देशक अरुण मथेश्वरन, पहली बार लीड रोल निभा रहे लोकेश कनगराज और प्रतिभाशाली अभिनेत्री वामिका गब्बी की तिकड़ी इस फिल्म को खास बनाती है। यह फिल्म पूरे भारत के दर्शकों को एक दमदार सिनेमाई अनुभव देने के सन पिक्चर्स के विज़न को आगे बढ़ाती है। फिल्म का निर्देशन अरुण मथेश्वरन ने किया है, जिन्होंने रॉकी, सानी कायिधम और कैप्टन मिलर जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है। डीसी उनके सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है। फिल्म में इमोशन और बड़े पैमाने का एक्शन शानदार तरीके से देखने को मिलेगा, जहां एक दर्दभरी प्रेम कहानी एक खूंखार गैंगस्टर ड्रामा के बीच आकार लेती है। टीज़र ने जहां इसकी दुनिया की झलक दिखाई थी, वहीं नया ट्रेलर ज़बरदस्त विज़ुअल्स, भावनात्मक पलों और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ फिल्म की भव्यता को और बढ़ा देता है। डीसी लोकेश कनगराज के करियर का एक अहम पड़ाव है क्योंकि वह पहली बार किसी फिल्म में मुख्य अभिनेता बने हैं।

अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी हुई साइबर ठगी की शिकार

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड जगत की मशहूर फिल्म अभिनेत्री और निर्माता कीर्ति कुल्हारी (43) के साथ साइबर धोखाधड़ी का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। अज्ञात अपराधियों ने उनके मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड का अनधिकृत एक्सेस हासिल कर महज कुछ ही मिनटों में 2,43,852 रुपए का फ्रॉड किया है। अभिनेत्री की शिकायत पर अंबोली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर दर्ज एफआईआर के अनुसार, अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी वर्सोवा इलाके में रहती हैं और अभिनय व फिल्म निर्माण के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं। यह घटना रात लगभग 9:31 बजे की है। उस समय वह अंधेरी पश्चिम में फन रिपब्लिक मॉल के पास स्थित सिनेपोलिस थिएटर में थीं। इसी दौरान उनके मोबाइल नंबर पर बैंक के क्रेडिट कार्ड से एयरोमेक्सिको एयरलाइन पर 2,525 अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अलर्ट मैसेज प्राप्त हुआ। अनजान और संदिग्ध विदेशी लेनदेन का मैसेज देखते ही अभिनेत्री ने बिना समय गंवाए बैंक के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया। बैंक अधिकारियों ने जांच के बाद बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड से बिना अनुमति के चार अलग-अलग बड़े ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा के तौर पर तुरंत कार्ड ब्लॉक कर दिया गया।

पीड़ित अभिनेत्री ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड पूरी तरह गोपनीय था, जिसे उन्होंने किसी के साथ साझा नहीं किया था। आशंका जताई जा रही है कि किसी डिजिटल मालवेयर या स्पाईवेयर के जरिए उनका फोन और कार्ड हैक किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंबोली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की टीम बैंक रेफरेंस नंबरों और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें कि अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी ने 'पिंक', 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक', 'इंदु सरकार', 'मिशन मंगल' और 'क्रिमिनल जस्टिस' जैसी हिट फिल्मों में जबरदस्त अभिनय किया है।

प्रदर्शन

जम्मू में शुक्रवार को पीओजेके में हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन करते विस्थापित समुदाय के लोग। प्रदर्शनकारियों के हाथों में जम्मू से पीओजेके, हम वापस लौटेंगे! और मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ में गिलगित स्काउट्स का गठन करो जैसे बैनर-पोस्टर मौजूद रहे।

एक्ट्रेस से अब प्रेजेंटर बनीं सोनाली बेंद्रे

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड में कई सालों तक अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से दिल जीतने वाली सोनाली बेंद्रे अब एक नए रोल में नजर आएंगी। दरअसल, वह अब अभिनय के साथ-साथ अच्छी कहानियों को आगे बढ़ाने का काम भी करना चाहती हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने फिल्म 'सोलह' के साथ प्रेजेंटर के तौर पर अपना सफर शुरू किया है। बता दें कि प्रेजेंटर का मतलब होता है वो शख्स जो किसी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करे। वो फिल्म का चेहरा बनता है और लोगों को बताता है कि ये कहानी क्यों जरूरी है। सोनाली अपने इस रोल को लेकर काफी उत्साहित हैं। आईएएनएस से खास बातचीत में सोनाली बेंद्रे ने बताया कि 'सोलह' उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्हें हमेशा से ऐसी कहानियां पसंद रही हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहें। ऐसी कहानियां जो आपको एक जगह बैठकर सोचने पर मजबूर कर दें। 'सोलह' में ये सब है, इसलिए जब उन्होंने पहली बार इस फिल्म की कहानी सुनी तो वो तुरंत उससे जुड़ गईं। सोनाली ने कहा, ''फिल्म को प्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यह मेरे लिए एक नए सफर की शुरुआत है। मैंने हमेशा ऐसी कहानियों को चुना है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिल और दिमाग में रह जाती हैं। जो आपको थोड़ी देर के लिए रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं। आपको जिंदगी को थोड़ा अलग तरीके से देखने में मदद करती हैं। 'सोलह' ने मेरे साथ बिल्कुल यही किया। इसे सुनने के बाद मैं काफी देर तक शांत रही और सोचती रही।'' सोनाली ने बताया कि आखिर उन्हें 'सोलह' की कहानी इतनी क्यों पसंद आई। ''जब मैंने पहली बार कहानी सुनी तो वो सीधे मेरे दिल से जा लगी। असल में ये फिल्म उम्मीद की कहानी है। ये हिम्मत की कहानी है और सबसे जरूरी बात ये आम लोगों के अंदर छिपी उस शांत ताकत की कहानी है, जिसके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात नहीं करते। पिछले कुछ सालों में मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है।

अच्छे लोगों के साथ काम करो, हार्डी संधू की इस सलाह ने बदला रेवती महुरकर का नजरिया

मुंबई/एजेन्सी

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके सिंगर और एक्टर हार्डी संधू न सिर्फ अपनी आवाज और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने प्रोफेशनल व्यवहार के लिए भी फेमस हैं। उनके साथ काम करने वाले हर कलाकार अक्सर उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। अब एक्ट्रेस रेवती महुरकर ने भी हार्डी के साथ अपने अनुभव को शेयर किया। रेवती ने बताया कि 'तेवर' म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान हार्डी ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी, जिसे वो आज भी अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती हैं। रेवती महुरकर ने बताया कि हार्डी संधू ने उन्हें इंडस्ट्री में टिके रहने का सबसे जरूरी मंत्र दिया। उन्होंने कहा, ''शूट के बीच में हार्डी ने कहा, 'अपने काम को लेकर बहुत सोच-समझ कर फैसला लिया करो। 'हमेशा अच्छे कलाकारों और अच्छी टीम के साथ ही काम करना', इस एक सलाह ने मेरे काम चुनने का पूरा तरीका बदल दिया।''

उन्होंने कहा, ''हार्डी के साथ काम करने के बाद मुझे असल में समझ आया कि आप किन लोगों के साथ काम करते हैं, ये कितना मायने रखता है।

अक्सर हम सिर्फ प्रोजेक्ट देखते हैं, लेकिन टीम और माहौल को इग्नोर कर देते हैं। हार्डी के साथ शूट पर मुझे महसूस हुआ कि एक अच्छा प्रोडक्शन कैसा होता है। उनके सेट पर हर चीज प्रोफेशनल थी। उनका प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल का था।''

रेवती ने टीम के व्यवहार की भी

बात की। उन्होंने कहा, ''सबसे खास बात ये थी कि उनकी पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सम्मान से बात की। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं नई हूं।

मुझे हर फैसले में बराबर की अहमियत मिली। शूट के दौरान हम अच्छे दोस्त बन गए और इसकी सबसे बड़ी वजह हार्डी हैं। वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका दिमाग बहुत क्रिएटिव है और वो हर चीज को नए तरीके से सोचते हैं। उनके साथ बैठकर बात करना भी बहुत कुछ सिखाता है।''

रेवती ने हार्डी के व्यक्तित्व के बारे में आगे कहा, ''वह इंडस्ट्री की राजनीति से दूर रहते हैं। वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। इसी वजह से 'तेवर' का फाइनल रिजल्ट आज भी मेरे दिल के सबसे करीब है। ये अब तक का मेरा सबसे पसंदीदा काम है। जब भी मैं वो वीडियो देखती हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है।''

रेवती ने शूटिंग के आखिरी दिन की एक बहुत प्यारी याद भी साझा की। उन्होंने बताया कि शूट 48 घंटे तक लगातार चला था। इतनी लंबी शूट के बाद भी टीम में एक अलग ही एनर्जी थी।

रेवती ने याद करते हुए कहा, ''48 घंटे नॉन-स्टॉप शूट करने के बाद हम सब बहुत थक गए थे, लेकिन जब पैकअप हुआ तो हार्डी ने कहा रुको, अभी नहीं। फिर हार्डी, हमारे कोरियोग्राफर, मेरे मैनेजर और मैं हम चारों ने फैसला किया कि हम थोड़ी देर और साथ बैठेंगे। हमें सुबह मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उससे पहले तक हम सब साथ रहे। हमने खूब बातें कीं, खाना खाया, म्यूजिक सुना और हंसे। उस रात जो बॉन्ड बना वो आज तक है। ये दिखाता है कि अगर टीम अच्छी हो तो काम बोझ नहीं लगता।' अब बात करते हैं हार्डी संधू के आने वाले प्रोजेक्ट की। हार्डी जल्द ही पंजाबी फिल्म 'रांझेया' में लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म एक लव स्टोरी है। इस फिल्म में उनके साथ सिमरत कौर रंधावा और अंगद बेदी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।

चातुर्मास आत्मा को परमात्मा बनाने की दिव्य साधना का पर्व : आचार्यश्री रविशेखरसूरी

चेन्नई/दक्षिण भारत । राजस्थान के जीरावला तीर्थ में आचार्यश्री हिमाचलसूरीश्वरजी के शिष्य पंन्यासश्री रत्नाकरविजयजी के शिष्य आचार्यश्री रविशेखरसूरीश्वरजी व ललितशेखरसूरीश्वरजी एवं साध्वी श्री संजयशीलाश्रीजी का हर्षोल्लास से चातुर्मास प्रवेश हुआ। चातुर्मास आयोजन के लाभार्थी चेन्नई निवासी कंचनबाई केसरीमल भंडारी परिवार ने संतों का स्वागत किया। इस मौके पर आचार्यश्री रविशेखरसूरीश्वरजी ने कहा कि चातुर्मास आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना का स्वर्णिम अवसर है। यह काल आत्माध्ययन, आत्मनिरीक्षण, स्वचिंतन, मनन, आत्मज्ञान तथा गुरुभगवंतों की निश्रा में स्वाध्याय और संयममय जीवन जीने का श्रेष्ठ समय है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से चातुर्मास को जीवन-परिवर्तन का माध्यम बनाने का आह्वान किया। इस वर्ष के चातुर्मास में लगभग 475 आराधक विभिन्न तप, जप, स्वाध्याय एवं अन्य आराधनाओं में भाग लेकर 50 दिनों तक धर्मसाधना करेंगे।

शत्रुंजय महातीर्थ की आराधना आत्मा को सिद्धत्व की ओर ले जाती है: आचार्य हीरचंद्रसूरीश्वर

चेन्नई/दक्षिण भारत । जैन आराधना भवन, साहुकारपेट में आयोजित प्रवचन सभा में आचार्यश्री हीरचंद्रसूरीश्वरजी ने शुक्रवार को शत्रुंजय महातीर्थ की अनुपम महिमा तथा श्रावक धर्म के जीवन-मूल्यों पर प्रवचन देते हुए कहा कि शत्रुंजय महातीर्थ पंचम दुर्लभ तीर्थों में से एक परम पावन तीर्थ है।

इस महान तीर्थ की भावपूर्ण आराधना तथा दर्शन-वंदन से जीव पंचम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी बन सकता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि हमारा जन्म दुःषम पंचम काल में हुआ है, फिर भी शत्रुंजय जैसे परम पावन महातीर्थ तथा तारक परमात्मा का सानिध्य मिलना हमारे असंख्य पूर्वजन्मों के महान पुण्य का परिणाम है।

शत्रुंजय महातीर्थ अनंत-अनंत सिद्धात्माओं की तपोभूमि एवं सिद्धभूमि है, जहां श्रद्धापूर्वक चरण रखते ही आत्मा में शुभ भावों का अद्भुत जागरण होता है और मोक्षमार्ग के प्रति दृढ़ प्रेरणा प्राप्त होती है। श्रावक धर्म के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सच्चा श्रावक वही है, जो अटूट श्रद्धा, विनय और भक्ति के साथ जिनवाणी का श्रवण करता है तथा उसे अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करता है।

उन्होंने 'न्याय-संपन्न वैभव' का महत्व समझाते हुए कहा कि धर्मकार्य अथवा दान में कभी भी अन्यायपूर्वक अर्जित धन का उपयोग नहीं होना चाहिए। न्याय और ईमानदारी से अर्जित धन को ही धर्म के सात क्षेत्रों में समर्पित करना चाहिए। 'सुगुरु सेवा' पर प्रकाश डालते हुए आचार्यश्री ने कहा कि सद्गुरु की केवल बाह्य सेवा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अंतःकरण से उनका सम्मान करना, उनकी आज्ञाओं एवं उपदेशों को सहर्ष शिरोधार्य करना ही वास्तविक गुरु-भक्ति और सच्चा 'सुगुरु योग' है। धर्मसभा में उपस्थित श्रद्धालुओं ने अत्यंत श्रद्धा एवं एकाग्रता के साथ प्रवचन श्रवण कर धर्म, गुरु-भक्ति और मोक्षमार्ग पर चलने का प्रेरणास्पद संदेश ग्रहण किया।

श्रद्धा और शांति का मार्ग ही है आत्मविकास का सच्चा पथ - आचार्य कुलबोधिसूरीश्वर

चेन्नई/दक्षिण भारत । शहर के वेपेरी श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ के चातुर्मासिक प्रवास के दौरान गौतम किरण प्रांगण में आयोजित प्रवचन में आचार्य श्री कुलबोधिसूरीश्वरजी ने कहा कि इस चातुर्मास में स्वाध्याय का मुख्य ग्रंथ 'शांत सुधारस' रहेगा। भगवान महावीर की परंपरा के योगी पुरुष महामहोपाध्याय विनय विजय म. द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ अपने प्रथम श्लोक में ही संपूर्ण विश्व के कल्याण की मंगलकामना करता है।

आचार्यश्री ने जीवन की चार यात्राओं का विवेचन करते हुए कहा कि पहली यात्रा सिद्धि (सफलता) की है। अधिकांश लोग जीवनभर सफलता के पीछे दौड़ते रहते हैं। सफलता मिलती है तो प्रसन्नता होती है, लेकिन असफलता मिलते ही मनुष्य निराशा और हताशा से भर जाता है। दूसरी यात्रा बुद्धि की है। आज का मनुष्य हर स्थान पर केवल बुद्धि का उपयोग करता है, जबकि धर्म और जिनवाणी को समझने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। प्रवचन सुनने आते समय बुद्धि को बाहर और हृदय को भीतर लेकर आना चाहिए। बुद्धि के पास तर्क होता है, जबकि हृदय के पास श्रद्धा होती है।

आचार्यश्री ने माता-पिता का सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि पिता परिवार का हेड होता है, जबकि माता परिवार का हार्ट होती है। पिता बुद्धि से निर्णय लेता है, जबकि माता हृदय से प्रेम और करुणा का संसार बसाती है। आज हमारे घरों में केवल कार्य होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह किस भावना और तरीके से हुआ, यह अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश विवाद इसी कारण उत्पन्न होते हैं। आचार्यश्री ने प्रेरणा दी कि जब भी कोई शुभ कार्य, तप, आराधना या धर्मसाधना करनी हो, तब केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि हृदय से निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने तीसरी यात्रा शक्ति की बताते हुए कहा कि मनुष्य सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य की बाहरी यात्राओं में उलझा रहता है। ये सभी बाह्य उपलब्धियाँ हैं। इसके बाद उन्होंने चौथी और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शांति की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि अब समय बाहरी नहीं, बल्कि अंतर्यात्रा का है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति शक्ति के पीछे दौड़ता है, उसे शांति के अलावा सब कुछ मिल सकता है; लेकिन जो शांति के पीछे चलता है, उसे अंततः सब कुछ प्राप्त हो जाता है।

प्रवचन के दौरान पंन्यास ज्ञानबोधिविजयजी ने कहा कि जिनशासन में जिनबिंब और जिनागम दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने आचार्य हरिभद्रसूरिश्वरजी द्वारा रचित 'ललित विस्तारा' ग्रंथ की महत्ता बताते हुए कहा कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्रभु तक पहुंचने का दिव्य मार्गदर्शक है। इसके माध्यम से भगवान के स्वरूप, उनके उपदेश और मोक्षमार्ग का सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि यदि हमें जिनागम प्राप्त नहीं हुए होते, तो मोक्ष का मार्ग पहचानना अत्यंत कठिन हो जाता। केवल भगवान की पूजा करना नहीं, बल्कि प्रवचन श्रवण और स्वाध्याय का महत्व उससे भी अधिक है, क्योंकि जिनवाणी ही जीवन को सही दिशा देती है।

भगवान महावीर ने स्वाध्याय के पांच अंग बताए हैं, जिनमें 'पुनरावर्तन' (बार-बार दोहराना) का विशेष महत्व है। जो कुछ हम सुनते हैं, उसका बार-बार मनन करें, पुनरावर्तन करें और दूसरों के साथ साझा करें। निरंतर पुनरावर्तन से ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कि 'ललित विस्तारा' जैसा ग्रंथ अत्यंत विश्वसनीय है, क्योंकि हमें उसके रचयिता आचार्य पर पूर्ण विश्वास है।

चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने फिर रचा इतिहास, कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाया

चेन्नई/दक्षिण भारत। स्थानीय चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार को बल्क कार्गो हैंडलिंग में कई माइलस्टोन बनाकर एक बार फिर अपनी ऑपरेशनल कौशल का प्रदर्शन किया जिससे कुशल और कस्टमर-सेंट्रिक कार्गो ऑपरेशन के लिए भारत के लीडिंग पोर्ट्स में से एक के रूप में इसकी पोज़िशन पक्की हो गई है। चेन्नई पोर्ट ने जवाहर डॉक-2 पर जहाज़ एमवी नफीसा जहाज के ज़रिए एक ही दिन में 46,000 मीट्रिक टन बैरीट्स एक्सपोर्ट हैंडल करके ऑल-टाइम रिकॉर्ड बनाया। एक और अहम उपलब्धि जोड़ते हुए, चेन्नई पोर्ट ने उसी दिन जवाहर डॉक-4 पर जहाज एमवी अगिया चारिस के ज़रिए 13,208 मेट्रिक टन पिग आयरन, जो एक नई कार्गो कमोडिटी है, को सफलतापूर्वक हैंडल किया। चेन्नई पोर्ट के कार्गो हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करते हुए चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सचिन एस. कुर्वे ने तीन ऑपरेशन क्रेन का उद्घाटन किया। चेयरमैन सचिन ने पोर्ट अथॉरिटी के सभी स्टेकहोल्डर्स को बधाई दी और कहा कि ये माइलस्टोन चेन्नई पोर्ट के ऑपरेशनल एक्सीलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और कस्टमर-फोकस्ड इनिशिएटिव्स की लगातार कोशिश को दिखाते हैं।

जयगोपाल गरोड़िया विवेकानंद विद्यालय में मनाई गई गुरु पूर्णिमा

चेन्नई/दक्षिण भारत। शहर के अन्ना नगर के जयगोपाल गरोडिया विवेकानंद विद्यालय के विद्यार्थियों ने गुरुवार को धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई। यह दिन टीचरों के लोगों और समाज पर पड़ने वाले बदलाव लाने वाले असर की याद दिलाता है, जो मिलकर शुक्रगुज़ारी और तारीफ़ की भावना को बढ़ावा देता है।

कोला पेरुमल चेट्टी वैष्णव सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर, आर. मीना मेहता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। एकेडमिक डायरेक्टर जी. विजयकुमार और प्रिंसिपल एम. उमा इस मौके पर मौजूद थे। विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मुख्य अथिति मेहता ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला।

लक्ज़री फ़ैशन का खजाना लेकर आ रही हाई लाइफ़

चेन्नई/दक्षिण भारत। फैशन और स्टाइल के लिए मशहूर हाई लाइफ़ प्रदर्शनी का आगाज 4 अगस्त को हयात रीजेंसी में होगा। यह 5 अगस्त को भी जारी रहेगी।

इसके आयोजकों ने बताया कि चेन्नई का सबसे पसंदीदा डिज़ाइनर शॉपिंग डेस्टिनेशन आ गया है। इसका कई दिन पहले से ही इंतजार किया जाता है। भारत के मशहूर डिज़ाइनर्स के मॉडर्न कपड़े, शानदार एथनिक वियर, हाथ से बनी ज्वेलरी, स्टाइलिश एक्सेसरीज़ और भी बहुत कुछ के साथ लक्ज़री फ़ैशन की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि यहां लेटेस्ट ट्रेंड्स, बेहतरीन कारीगरी और खास स्टाइल सबकुछ एक ही जगह से प्राप्त कर सकते हैं।

जिनेश्वर देव ने अभयदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना : जयतिलक मुनि

चेन्नई। शहर के साहुकारपेट स्थित एसएस जैन संघ के तत्वावधान में जैन भवन में विराजित आचार्यश्री जयमलजी शिष्य संतश्री जयतिलक मुनिजी ने प्रवचन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभयदान सब दानों में श्रेष्ठ हैं, यह दान निर्भय होकर दिया जाता है। धर्म मनुष्य को केवल पूजा-पाठ ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला प्रकाश स्तंभ है। भगवान महावीर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। वर्तमान समय में मनुष्य भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति में लगा हुआ है, लेकिन आत्मिक शांति से दूर होता जा रहा है। आत्मा की उन्नति के लिए धर्म, संयम और सदाचार का मार्ग अपनाना आवश्यक है।

संतश्री ने कहा कि समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, परंतु जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में उतारता है, वही वास्तविक अर्थों में सफल कहलाता है। धर्म मनुष्य को विनम्रता, करुणा, क्षमा और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.